



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 177] नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 21, 1995/वैशाख 1, 1917  
No. 177] NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 21, 1995/VAISAKHA 1, 1917

चित्त मंत्रालय  
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 अप्रैल, 1995

आयकर

आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान  
के परिहार के लिए भारत गणराज्य  
और

स्विस कन्फेडरेशन के बीच करार  
भारत गणराज्य की सरकार

तथा

स्विस फेडरल काउन्सिल

आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार के  
लिए एक करार सम्पन्न करने की इच्छा से,

नीचे लिखे अनुसार सहमत हुई है :

अनुच्छेद 1

वैयक्तिक क्षेत्र

यह करार उन व्यक्तियों पर लागू होगा जो संबिदाकारी  
राज्यों में से किसी एक अथवा दोनों के निवासी हैं।

सा. का. नि. 357(अ):—यतः आय पर करों के  
संबंध में दोहरे कराधान के परिहार और राजस्व अपवंचन को  
रोकने के लिए भारत गणराज्य की सरकार और स्विस परि-  
संघ की सरकार के बीच संलग्न करार, उक्त करार के  
अनुच्छेद 26 के पैराग्राफ 1 के अनुसार करार को लागू  
करने के लिए दोनों ही सरकारों के कानूनों के तहत अपेक्षित  
प्रक्रियाओं के पुरा हो जाने के संबंध में दोनों संबिदाकारी  
राज्यों द्वारा एक-दूसरे को अधिसूचना जारी कर दिए जाने के  
बाद 20 दिसम्बर, 1994 को लागू हो गया है ;

अतः, अब, आयकर अधिनियम 1961 (1961 का  
43) की धारा 90 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए  
केन्द्रीय सरकार एतद्वारा निदेश देती है कि उक्त करार के  
सभी उपबंधों को भारत संध में लागू किया जाए।

## अनुच्छेद 2

करार के अंतर्गत आने वाले कर

1. जिन करों पर यह करार लागू होगा, वे इस प्रकार हैं :

(क) भारत के मामले में :

आयकर जिसमें उस पर लगने वाला कोई अधिभार भी शामिल है ;

(ख) स्विटजरलैण्ड के मामले में :

आय पर फेडरल, कन्टोनल तथा कम्यूनल कर (सकल आय, अर्जित आय, पूंजी से आय, औद्योगिक तथा वाणिज्यिक लाभ पूंजीगत अभिलाभ तथा आय की अन्य मदें)

2. यह करार संविदाकारी राज्यों में से किसी के द्वारा किसी भी समरूप अथवा सारतः इसी तरह के करों पर भी लागू होगा, जो वर्तमान करार पर हस्ताक्षर किए जाने के पश्चात् इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 में वर्णित करों के अतिरिक्त अथवा उनके स्थान पर लगाए जाएंगे ।

3. इस करार में, “भारतीय कर” मद से अभिप्रेत है भारत द्वारा लगाया गया ऐसा कर जिस पर यह करार लागू होता है, “स्विस कर” पद से अभिप्रेत है स्विटजरलैण्ड द्वारा लगाया गया ऐसा कर जिस पर यह करार लागू होता है तथा “कर” पद से अभिप्रेत है भारतीय कर अथवा स्विस कर, जैसा कि संदर्भ के अनुसार अपेक्षित हो परन्तु इस अनुच्छेद के पूर्ववर्ती पैराग्राफों के करों में, जिनपर यह करार लागू होता है, संविदाकारी राज्यों में से किसी भी राज्य में करों में संबंधित लागू कानूनों के अंतर्गत लगाए जाने वाला कोई अर्थदण्ड अथवा ध्याज शामिल नहीं होगा ।

4. संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी ऐसे किसी महत्वपूर्ण परिवर्तनों के बारे में एक-दूसरे को सूचित करेंगे जो उनके अपने संगत संबंधित कराधान कानूनों में किए गए हों ।

## अनुच्छेद 3

सामान्य परिभाषाएं

1. इस करार में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो :

(क) “भारत” पद से अभिप्रेत है—भारत का राज्य-क्षेत्र तथा उसमें शामिल राज्य क्षेत्रीय समुद्र तथा उसके ऊपर का वायुमण्डलीय क्षेत्र और कोई भी अन्य समुद्री क्षेत्र जिस पर भारतीय कानून तथा अन्तरराष्ट्रीय कानूनों के अनुसार भारत के प्रभु-सत्ता-सम्पन्न अधिकार, अन्य अधिकार तथा क्षेत्राधिकार हों;

(ख) “स्विटजरलैण्ड” पद से अभिप्रेत है—स्विस महासंघ ;

(ग) “एक संविदाकारी राज्य” और “दूसरे संविदाकारी राज्य” पदों से, संदर्भ की अपेक्षा के अनुसार भारत अथवा स्विटजरलैण्ड अभिप्रेत है ;

(घ) “व्यक्ति” पद में शामिल है कोई व्यक्ति, कोई कंपनी, व्यक्तियों का कोई निकाय अथवा कोई अन्य ऐसा अस्तित्व जो संविदाकारी राज्यों में से किसी भी राज्य में लागू कानूनों के अंतर्गत कराधेय हो;

(ङ) “कंपनी” पद से अभिप्रेत है—ऐसा कोई निगमित निकाय अथवा कोई सत्ता जो संबंधित संविदाकारी राज्यों के कराधान कानूनों के अंतर्गत एक कंपनी मानी जाती है ;

(च) “एक संविदाकारी राज्य का उद्यम” तथा “दूसरे संविदाकारी राज्य का उद्यम” पदों से क्रमशः एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा संचालित कोई उद्यम अभिप्रेत है ;

(छ) “सक्षम प्राधिकारी” पद से अभिप्रेत है—भारत के मामले में, केन्द्रीय सरकार का राजस्व विभाग अथवा उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि तथा स्विटजरलैण्ड के मामले में, संघीय कर प्रशासन का निदेशक अथवा उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि;

(ज) “राष्ट्रिक” पद से अभिप्रेत है;—किसी संविदाकारी राज्य की राष्ट्रीयता धारण करने वाला कोई व्यक्ति तथा कोई कानूनी व्यक्ति, भागीदारी और संस्था जिसे अपनी यह हैसियत किसी संविदाकारी राज्य में प्रवृत्त कानूनों से उस रूप में प्राप्त होती हो ;

(झ) “अन्तरराष्ट्रीय यातायात” पद से अभिप्रेत है—किसी ऐसे वायुयान द्वारा कोई भी परिवहन जो एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा संचालित हो, सिवाय उस स्थिति के जब वायुयान केवल दूसरे संविदाकारी राज्य के बीच ही चलाया जाता हो ;

(ञ) “वायुयान के प्रचालन” पद से अभिप्रेत है—वायुयान के मालिकों अथवा पट्टेदारों अथवा चार्टररों द्वारा यात्रियों, डाक, पशुधन अथवा माल को हवाई मार्ग से लाने-ले-जाने का कारोबार, जिसमें अन्य उद्यमों की ओर से ऐसे परिवहन के लिए टिकटों की बिक्री, वायुयान का प्रासंगिक पट्टा और ऐसे परिवहन से प्रत्यक्षतः संबंधित कोई अन्य कार्यकलाप भी शामिल है ;

(ट) “वित्त वर्ष” पद से अभिप्रेत है :

(i) भारत के मामले में, भारतीय आयकर अधिनियम में यथा-परिभाषित “पूर्व वर्ष”; तथा

(ii) स्विटजरलैण्ड के मामले में, कैलेण्डर वर्ष ।

2. किसी संविदाकारी राज्य द्वारा इस करार के उपबंधों के प्रवर्तन के संबंध में, कोई ऐसा शब्द जो उसमें परिभाषित नहीं हुआ हो, जब तक इस संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित नहीं हो, तब तक वही अर्थ होगा जो उस राज्य में लागू कानूनों के अंतर्गत उन करों से संबंधित है जो इस करार के विषय हैं ।

#### अनुच्छेद 4

##### वित्तीय अधिवास

1. इस करार के प्रयोजनों के लिए, 'किसी संविदाकारी राज्य का निवासी' पद से अभिप्रेत है—कोई भी ऐसा व्यक्ति जिस पर उस राज्य के कानून के अंतर्गत, उसके अधिवास, निवास, निगमन-स्थान, प्रबंध-स्थान अथवा इस प्रकार की किसी अन्य कसौटी के कारण वहां कर लगाया जा सकता है ।

2. जहां पैराग्राफ 1 के उपबंधों के कारण, कोई व्यक्ति दोनों संविदाकारी राज्यों का निवासी हो तो उस स्थिति में इस करार के प्रयोजनों के लिए उसके निवास की हैसियत निम्नलिखित नियमों के अनुसार निश्चित की जाएगी :

(क) उसे उस संविदाकारी राज्य का निवासी माना जाएगा जहां उसे स्थायी निवास उपलब्ध हो, यदि उसे दोनों संविदाकारी राज्यों में कोई स्थायी निवास-गृह उपलब्ध हो, तो वह उस संविदाकारी राज्य का एक निवासी माना जाएगा जिसके साथ उसके व्यक्तिगत और आर्थिक संबंध घनिष्ठतर हैं (इस करार में उसके पश्चात् इन्हें उसके "महत्वपूर्ण हितों का केन्द्र" कहा गया है) ;

(ख) यदि उस संविदाकारी राज्य का, जिसमें उसके महत्वपूर्ण हित निहित हैं, निश्चय नहीं किया जा सकता हो, अथवा यदि उसका दोनों संविदाकारी राज्यों में से किसी भी संविदाकारी राज्य में कोई स्थायी निवास-गृह नहीं हो, तो वह उस संविदाकारी राज्य का निवासी माना जाएगा जिसमें वह आदतन रहता हो;

(ग) यदि उसका स्थायी आवास दोनों संविदाकारी राज्यों में है अथवा उसमें से किसी भी राज्य में नहीं है, तो वह उस संविदाकारी राज्य का निवासी माना जाएगा, जिसका वह एक राष्ट्रिक है ;

(घ) यदि वह दोनों संविदाकारी राज्यों का राष्ट्रिक है अथवा उनमें से किसी का भी राष्ट्रिक नहीं है, तो संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी पारस्परिक सहमति द्वारा इस प्रश्न को सुलझावेंगे ।

3. जहां व्यक्ति से भिन्न कोई व्यक्ति पैराग्राफ 1 के उपबंधों के कारण, दोनों संविदाकारी राज्यों का निवासी हो तो वह उस संविदाकारी राज्य का निवासी माना जाएगा, जिसमें उसका वास्तविक प्रबंध-स्थान स्थित है ।

#### अनुच्छेद 5

##### स्थायी संस्थापन

1. इस करार के प्रयोजनों के लिए, "स्थायी संस्थापन" पद से कारोबार का वह निश्चित-स्थान अभिप्रेत है, जिसके द्वारा किसी उद्यम का कारोबार सम्पूर्णतः अथवा अंशतः चलाया जाता है ।

2. "स्थायी संस्थापन" पद में विशेषतया निम्नलिखित शामिल होंगे :

(क) प्रबंध का कोई स्थान ;

(ख) कोई शाखा ;

(ग) को कार्यालय ;

(घ) कोई भण्डार अथवा कोई अन्य बिक्री केन्द्र ;

(ङ) कोई कारखाना ;

(च) कोई कार्यशाला ;

(छ) कोई भाण्डागार जिसमें कोई व्यक्ति दूसरों के लिए भण्डारण सुविधाएं मुहैया करता हो ;

(ज) स्थायी बिक्री प्रदर्शनी केन्द्र ;

(झ) कोई खान, कोई तेल अथवा गैस का कुआं अथवा प्राकृतिक संसाधनों के निष्कर्षण का कोई अन्य स्थान ;

(ञ) कोई भवन-स्थल अथवा कोई निर्माण कार्य, प्रतिष्ठापन अथवा संयोजन परियोजना अथवा उनसे संबंधित पर्यवेक्षी कार्यकलाप, जहां ऐसा स्थल, परियोजना अथवा पर्यवेक्षी कार्यकलाप छः माह से अधिक अवधि के लिए जारी रहते हैं ;

(ड) कोई प्रतिष्ठापन अथवा संरचना, जिसका उपयोग प्राकृतिक संसाधनों की खोज अथवा विकास के लिए 90 दिन से अधिक दिनों तक किया जाता हो ;

(ठ) किसी उद्यम के द्वारा कर्मचारियों अथवा अन्य कामिकों के माध्यम से किसी संविदाकारी राज्य के अन्दर अनुच्छेद 12 में यथा परिभाषित शामिल सेवाओं से भिन्न की गई सेवा, परन्तु केवल यदि :

(1) किसी बारह महीने की अवधि में कुल मिलाकर 90 दिन से अधिक की अवधि अथवा अवधियों के लिए उस राज्य के अन्दर जारी उसी स्वरूप के किये गये कार्यकलाप ; अथवा

(2) किसी बारह महीने की अवधि में 30 दिन की अवधि से अधिक की अवधि अथवा अवधियों के लिए किसी संबंधित उद्यम (अनुच्छेद-9 के पैराग्राफ 1 के अर्थ में) के लिए उस राज्य में सेवाएं की गई हों ।

3. “स्थायी संस्थापन” पद में निम्नलिखित को शामिल नहीं माना जायेगा :

- (क) किसी उद्यम के माल अथवा पण्यवस्तुओं के केवल भण्डारण अथवा प्रदर्शन के प्रयोजनार्थ मुविदाओं का उपयोग;
- (ख) केवल भण्डारण अथवा प्रदर्शन के प्रयोजनार्थ उद्यम के माल अथवा पण्यवस्तुओं के स्टॉक का रखरखाव;
- (ग) अन्य उद्यम के द्वारा मात्र संसाधन के उद्देश्य के लिए उद्यम के माल अथवा पण्यवस्तुओं के स्टॉक का रखरखाव;
- (घ) किसी उद्यम के लिए माल अथवा पण्यवस्तुओं का केवल श्रय करने अथवा सूचना एकत्र करने के प्रयोजनार्थ कारोबार के किसी निश्चित स्थान का रखरखाव;
- (ङ) उद्यम के लिए अनन्य रूप से विज्ञापन देने, सूचना प्रदान करने, अथवा वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए जो व्यापार अथवा कारोबार में अनन्य रूप से किसी प्रारम्भिक अथवा सहायक स्वरूप के कार्यकलाप हों, कारोबार के किसी निश्चित स्थान का रखरखाव।

4. एक व्यक्ति जो कि दूसरे संविदाकारी राज्य के संक्षम के लिए अथवा उसकी ओर से किसी संविदाकारी राज्य में कार्य करता है—किसी स्वतंत्र हैसियत के किसी एजेंट से भिन्न, जिस पर पैराग्राफ (5) लागू होता हो—उस उद्यम का प्रथमोलिखित संविदाकारी राज्य में स्थायी संस्थापन होना तभी माना जाएगा, यदि :

- (1) वह उस राज्य में, उद्यम के लिए अथवा उसकी ओर से बातचीत करने तथा संविदा संपन्न करने का आभ्यासिक रूप से प्राधिकार रखता हो, जब तक कि उसके कार्यकलाप उद्यम के लिए माल अथवा पण्यवस्तुओं के श्रय तक ही सीमित न हों; अथवा
- (2) वह प्रथमोलिखित संविदाकारी राज्य में माल अथवा पण्यवस्तुओं का आभ्यासिक रूप से कोई स्टॉक रखता हो जिसमें से वह उद्यम के लिए अथवा उसकी ओर से नियमित रूप से माल अथवा पण्यवस्तुओं की डिलीवरी करता हो; अथवा
- (3) ऐसा करते समय, वह उस राज्य में उद्यम के माल अथवा पण्यवस्तुओं को उद्यम के लिए निर्मित अथवा संसाधित करता हो, बशर्ते कि इस प्रकार निर्मित अथवा संसाधित किए गए माल अथवा पण्यवस्तुओं के संबंध में ही यह प्रावधान लागू होगा।

5. एक संविदाकारी राज्य के उद्यम का दूसरे संविदाकारी राज्य में मात्र इस कारण कोई स्थायी संस्थापन होना नहीं माना जाएगा कि वह उस दूसरे राज्य में किसी दलाल, सामान्य कमीशन एजेंट अथवा स्वतंत्र हैसियत वाले किसी

अन्य एजेंट से कारोबार करता है, जहां ऐसे व्यक्ति अपने कारोबार का काम सामान्य रूप से कर रहे हों। लेकिन, जब किसी ऐसे एजेंट के कार्यकलाप पूर्णतः अथवा प्रायः पूर्णतः स्वयं उस उद्यम की ओर से अथवा उद्यम तथा अन्य उद्यम के लिए समर्पित हों जो उसके द्वारा नियंत्रित होते हों अथवा उसके हित को नियंत्रित करते हों, तो उसे उस स्थिति में उस पैराग्राफ के अभिप्राय के अन्तर्गत एक स्वतंत्र हैसियत का एजेंट नहीं समझा जायेगा।

6. दि कोई कंपनी जो एक संविदाकारी राज्य का निवासी है, किसी ऐसे कंपनी को नियंत्रित करती है अथवा किसी कंपनी द्वारा नियंत्रित होती है, जो दूसरे संविदाकारी राज्य की निवासी है अथवा जो उस दूसरे संविदाकारी राज्य में (चाहे किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से अथवा अन्यथा) कारोबार करती है तो मात्र इस तथ्य से ही उन दोनों में से किसी कंपनी को स्वतः ही दूसरी कंपनी का स्थायी संस्थापन नहीं माना जायेगा।

#### अनुच्छेद 6

##### अचल संपत्ति से आय

1. अचल संपत्ति से आय उस संविदाकारी राज्य में कराधेय हो सकेगी जिसमें ऐसी संपत्ति स्थित हो।

2. “अचल संपत्ति” पद को उस संविदाकारी राज्य की विधि के अनुसार परिभाषित किया जाएगा जिसमें संबंधित संपत्ति स्थित है। इस पद में, किसी भी हालत में ये शामिल होंगे—अचल संपत्ति के उपसाधन के रूप संपत्ति, ऐसे कृषि और वानिकी में प्रयुक्त पशुधन तथा उपस्कर, ऐसे अधिकार जिन पर भू-संपत्ति संबंधी सामान्य कानून के उपबंध लागू होते हों, अचल संपत्ति को भोगने के अधिकार, खनिज भंडार, तेलकूप, खदान तथा प्राकृतिक संसाधनों, के निष्कर्षण के अन्य स्थानों के संचालन के लिए अथवा कार्य करने के अधिकार के प्रतिफल के रूप में परिवर्तनीय अथवा नियत अदायगियों के अधिकार। पोत तथा विमान अचल संपत्ति नहीं माने जायेंगे।

3. पैराग्राफ 1 के उपबंध, अचल संपत्ति के प्रत्यक्ष उपयोग, उसे किराये पर देने अथवा किसी अन्य प्रकार के प्रयोग से होने वाली आय पर लागू होंगे।

4. पैराग्राफ 1 और 3 के उपबंध किसी उद्यम की अचल संपत्ति से अर्जित आय पर और व्यावसायिक सेवाओं के निष्पादन के लिए प्रयुक्त अचल संपत्ति से अर्जित आय पर भी लागू होंगी।

#### अनुच्छेद 7

##### कारोबार से लाभ

1. एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के कारोबार के लाभों पर, अन्तर्राष्ट्रीय यातायात के जलयानों के प्रचालन से प्राप्त लक्ष्यों से भिन्न, केवल उसी राज्य में कर लगाया जाएगा जब तक कि वह उद्यम दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थिति किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से उस राज्य में

कारोबार नहीं करता हो। यदि उक्त उद्यम उपर्युक्त तरीके से कारोबार करता हो तो उक्त के लाभों पर दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकता है किन्तु उसके लाभों के उतने अंश पर ही लगेगा जो उस उद्यम को प्रत्यक्षतया अथवा अप्रत्यक्षतया उस स्थायी संस्थापन के कारण उत्पन्न हुए हों।

2. जहाँ एक संविदाकारी राज्य का कोई उद्यम दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार करता हो, तब वहाँ प्रत्येक संविदाकारी राज्य को ऐसे स्थायी संस्थापन के कारण ये लाभ हुए माने जायेंगे जिनके प्राप्त होना की तब अपेक्षा रहती, जब यह एक समान या मिलती-जुलती परिस्थितियों में एक-समान या मिलने-जुलने कार्यकलापों में लगा हुआ कोई निश्चित और भिन्न उद्यम होता और उस उद्यम के साथ पूर्णतः स्वतंत्र रूप से कारोबार करता, जिसका यह स्थायी संस्थापन है।

3. किसी स्थायी संस्थापन के लाभों का निर्धारण करने में, उन खर्चों की कटौती की अनुमति दी जाएगी जो स्थायी संस्थापन के प्रयोजनों के लिए उचित किए जाते हैं, भले ही ये उस राज्य में किए गए हों जहाँ स्थायी संस्थापन स्थित हो अथवा अन्यत्र किए गए हों। कार्यकारी तथा सामान्य प्रशासनिक खर्च उस राज्य के करारान कानूनों के अनुसार कटौतियों के रूप में अनुज्ञेय होंगे। तथापि, इस पैराग्राफ को कोई भी व्यवस्था ऐसे खर्चों के लिए किसी कटौती हेतु प्राधिकृत नहीं करेगी जो उस स्थिति में कटौती दिए जाने योग्य नहीं होता यदि स्थायी संस्थापन एक अलग उद्यम होता।

4. जहाँ किसी संविदाकारी राज्य में, उद्यम के कुल लाभों को उसके विभिन्न अंगों के प्रति अनुभाजन के आधार पर किसी स्थायी संस्थापन, के माने जाने वाले लाभों को निश्चित करने की प्रथा हो, वहाँ पैराग्राफ 2 की कोई भी व्यवस्था ऐसे संविदाकारी राज्य की ऐसी प्रचलित प्रभाजन पद्धति से, कर लगाने वाले लाभों को निश्चित करने से प्रतिबंधित नहीं करेगी। तथापि अपनाई गई प्रभाजन पद्धति ऐसी होगी कि उसका परिणाम इस अनुच्छेद में विहित विद्वान्तों के अनुसार होगा।

5. कोई लाभ, केवल इस कारण स्थायी संस्थापन को हुआ नहीं माना जाएगा कि उस स्थायी संस्थापन ने उद्यम के लिए माल अथवा पण्यवस्तुएं खरीदी हैं।

6. जहाँ आय की मदों में लाभों की वे मदें शामिल हैं जिनका इस करार के अन्य अनुच्छेदों में विवेचन किया गया है, वहाँ उन अनुच्छेदों के उपबंध इस अनुच्छेद के उपबंधों को प्रभावित नहीं करेंगे।

#### अनुच्छेद 8

##### वायु परिवहन

1. अन्तरराष्ट्रीय यातायात में वायुयानों के परिचालन से प्राप्त लाभों पर केवल उस संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकेगा जिसमें उद्यम का प्रभावी प्रबंध-स्थान स्थित हो।

2. पैराग्राफ 1 के उपबंध, किसी पूल, किसी संयुक्त कारोबार अथवा किसी अन्तरराष्ट्रीय परिवालन एजेंसी में भाग लेने से प्राप्त लाभों पर भी लागू होंगे।

#### अनुच्छेद 9

##### सहयोगी उद्यम

जहाँ

(क) एक संविदाकारी राज्य का कोई उद्यम दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के प्रबंध, नियंत्रण अथवा पूंजी में प्रयत्नः अथवा अप्रत्यक्षतः भाग लेता है; अथवा

(ख) वे ही व्यक्ति, एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम और दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के प्रबंध, नियंत्रण अथवा पूंजी में प्रयत्नः अथवा अप्रत्यक्षतः भाग लेते हैं;

और दोनों में से किसी भी अवस्था में, दोनों उद्यमों के बीच उनके वाणिज्यिक अथवा विनीय संबंधों में ऐसी शर्तें रखी अथवा लगायी जाती हैं, जो उन शर्तों से विन्न हैं, जो स्वतंत्र उद्यमों के बीच रखी जाती हैं, वहाँ ऐसा कोई भी लाभ जो उन शर्तों के नहीं होने की स्थिति में उन उद्यमों में से किसी एक उद्यम को प्राप्त हुआ होता, किन्तु उन शर्तों के कारण उस प्रकार प्राप्त नहीं हुआ, तो वे लाभ उक्त उद्यम के लाभों में शामिल किए जा सकेंगे और उन पर उदनुसार कर लगाया जा सकेगा।

#### अनुच्छेद 10

##### लाभांश

1. एक संविदाकारी राज्य की निवासी किसी कंपनी द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को अदा किए लाभांशों पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकता है।

2. तथापि, ऐसे लाभांशों पर उस संविदाकारी राज्य में भी, उस राज्य के कानूनों के अनुसार कर लगाया जा सकेगा जिसकी लाभांश अदा करने वाली कंपनी एक निवासी है, परन्तु यदि प्राप्तकर्ता, लाभांशों का हिताधिकारी स्वामी है, तो इस प्रकार लगाया गया कर लाभांशों की सकल रकम का 15% से अधिक नहीं होगा।

इस पैराग्राफ का उन लाभों के संबंध में कंपनी के कराधान पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, जिनमें से लाभांशों का भुगतान किया जाता है।

3. इस अनुच्छेद में यथा-प्रयुक्त "लाभांश" शब्द का अभिप्राय, शेयरों, "जेयोसेन्स" शेयर अथवा जेयोसेन्स राइट्स, खनन-शेयरों, प्रवर्तक के शेयरों अथवा अन्य अधिकारों से प्राप्त आय से है, जो लाभ की भागीदारी के ऋण-दावे नहीं हैं और अन्य निगमित अधिकारों से प्राप्त आय से है, जिस पर वही कराधान व्यवस्था लागू होती है, जो राज्य के कराधान कानून के अन्तर्गत शेयरों से प्राप्त आय के मामले में लागू होती है, जिसकी वितरण करने वाली कंपनी निवासी है।

4. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंध उस स्थिति में लागू नहीं होंगे यदि लाभांशों का हिताधिकारी स्वामी, जो एक संविदाकारी राज्य का निवासी है, दूसरे संविदाकारी राज्य में जिसकी लाभांश अदा करने वाली कंपनी एक निवासी है, वहां स्थित एक स्थायी संस्थापन के माध्यम से, कारोबार करना है, और जिस धारणाधिकार के बारे में लाभांशों की अदायगी की जाती है, ऐसे स्थायी संस्थापन के प्रभावी रूप से सम्बद्ध हो। ऐसे मामले में अनुच्छेद 7 के उपबंध लागू होंगे।

5. जहां कोई कंपनी, जो एक संविदाकारी राज्य की निवासी है, दूसरे संविदाकारी राज्य से लाभ अथवा आय प्राप्त करती है, वहां वह दूसरे राज्य कंपनी द्वारा अदा किए लाभांशों पर वहां तक किसी भी प्रकार का नहीं लगा सकता सिवाय उस स्थिति के जहां ऐसे लाभांश उस दूसरे राज्य के निवासी को अदा किए जाने हों, अथवा जिस धारणाधिकार के बारे में लाभांशों की अदायगी की जाती है, वह उस राज्य में वहां स्थित किसी स्थायी संस्थापन से प्रभावी रूप से संबंधित है, और न ही वहां उस दूसरे राज्य में कंपनी के अवितरित लाभों पर अवितरित लाभ संबंधी कर लगाया जाएगा, चाहे अदा किए गए लाभांश अथवा अवितरित लाभ पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से उस दूसरे राज्य में उद्भूत होने वाले लाभ अथवा आय के रूप में ही हों।

#### अनुच्छेद 11

##### ब्याज

1. एक संविदाकारी राज्य में उत्पन्न होने वाले तथा दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को अदा किए जाने वाले ब्याज पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा।

2. तथापि, ऐसे ब्याज पर उस संविदाकारी राज्य में भी उस राज्य के कानूनों के अनुसार कर लगाया जाएगा, जिस राज्य से यह उद्भूत होता है, परन्तु यदि प्राप्तकर्ता ब्याज का हिताधिकारी स्वामी हो, तो इस प्रकार लगाया गया कर ब्याज की सकल राशि के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

3. पैराग्राफ 2 के उपबंधों के हांतु हुए भी जहां ब्याज वास्तव में बैंकिंग व्यवसाय में लगे हुए किसी बैंक अथवा किसी ऐसे उद्यम को अदा किया जाता है जो ब्याज अदा करने वाली कंपनी की प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः पूंजी का कम से कम 20% अंश रखता हो, जो दूसरे संविदाकारी राज्य का निवासी हो और जो ब्याज के हिताधिकारी स्वामी है, उस संविदाकारी राज्य में, जिसमें यह ब्याज उद्भूत होता है, इस पर इस प्रकार लगाया गया कर ब्याज की सकल राशि के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

4. पैराग्राफ 2 और 3 के उपबंधों के हांतु हुए भी,

(क) स्विटजरलैण्ड में उद्भूत तथा भारत के किसी निवासी को अदा किए गए ब्याज पर केवल

भारत में ही कर लगाया जा सकेगा यदि हमकी अदायगी भारत के निर्यात-आयात बैंक अथवा संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारियों के बीच आदान-प्रदान किए गए पत्रों में विनिर्दिष्ट तथा अनुमति-प्राप्त किसी संस्थान द्वारा दिए गए ऋण, गारंटी अथवा बीमा अथवा क्रेडिट गारंटी के संबंध में हो;

(ख) भारत में उद्भूत तथा स्विटजरलैण्ड के किसी निवासी को अदा किए गए ब्याज पर केवल स्विटजरलैण्ड में तभी कर लगाया जा सकेगा यदि हमकी अदायगी स्विटजरलैण्ड के उपबंधों के तहत निर्यात अथवा निवेश जोखिम गारंटी को विनियमित करने हुए अथवा संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारियों के बीच आदान-प्रदान किए गए पत्रों में विनिर्दिष्ट तथा अनुमति-प्राप्त किसी संस्थान द्वारा दिए गए ऋण, गारंटी अथवा बीमा अथवा क्रेडिट गारंटी के संबंध में हो;

(ग) एक संविदाकारी राज्य में उत्पन्न होने वाले तथा दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी ऐसे निवासी, जो अन्तरराष्ट्रीय यातायात में विमान परिचालन में लगा हुआ हो, को अदा किया गया ब्याज केवल उसी अन्य राज्य में उस सीमा तक कराधेय होगा जितना ऐसे कार्यकलापों से जुड़ी हुई निधियों पर ब्याज अदा किया गया हो;

(घ) भारत में उत्पन्न होने वाले तथा स्विटजरलैण्ड के किसी निवासी को अदा किए गए ब्याज को भारतीय-कर से छूट प्राप्त होगी यदि ऋण अथवा अन्य कर्ज जिसके संबंध में ब्याज अदा किया जाता है कोई अनुमोदित ऋण हो। "अनुमोदित ऋण" शब्द से अभिप्रेत है—कोई ऋण अथवा इस निमित्त भारत सरकार द्वारा अनुमोदित अन्य कर्ज।

5. इस अनुच्छेद में यथा-प्रयुक्त "ब्याज" शब्द से अभिप्रेत है—प्रत्येक प्रकार के ऋण संबंधी दावों से प्राप्त आय, चाहे वे बंधक द्वारा प्रतिभूत हों अथवा नहीं हों और चाहे उन्हें ऋण-दाता के लाभों में भागीदारी का कोई अधिकार प्राप्त हो अथवा नहीं हो और विशेष रूप से सरकारी प्रतिभूतियों से प्राप्त आय और बंध-पत्रों अथवा ऋण-पत्रों से प्राप्त आय, जिसमें ऐसी प्रतिभूतियों, बंध-पत्रों अथवा ऋण-पत्रों से संबंधित प्रीमियम और पुरस्कार भी शामिल हों। देरी से किए गए भुगतान के लिए लगाए गए वांडिक प्रभारों को इस अनुच्छेद के प्रयोजनार्थ ब्याज के रूप में नहीं समझा जाएगा।

6. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंध उस स्थिति में लागू नहीं होंगे, यदि ब्याज का हिताधिकारी स्वामी, संविदाकारी राज्य का निवासी और दूसरे संविदाकारी राज्य में जिसमें ब्याज उत्पन्न हुआ हो, उसमें स्थित किसी स्थायी संस्थापन के

मध्यम से कारोबार करना हो, और जिस ऋण-दावे के संबंध में ब्याज अदा किया गया हो वह ऐसे स्थायी संस्थापन से प्रभावी रूप से संबद्ध हो। ऐसे मामले में अनुच्छेद 7 के उपबंध लागू होंगे।

7. किसी संविदाकारी राज्य में ब्याज उस स्थिति में उद्भूत हुआ समझा जाएगा जब ब्याज अदा करने वाला स्वयं वह संविदाकारी राज्य, उसका कोई राजनैतिक उप-प्रभाग, कोई स्थानीय प्राधिकरण अथवा उस राज्य का कोई निवासी हो। किन्तु, जहां ब्याज अदा करने वाले व्यक्ति का, चाहे वह किसी संविदाकारी राज्य का निवासी हो अथवा नहीं, संविदाकारी राज्य में एक स्थायी संस्थापन हो, जिसके संबंध में वह ऋण लिया गया था, जिस पर ब्याज की अदायगी की जाती है, और इस प्रकार का ब्याज इस प्रकार के स्थायी संस्थापन द्वारा वहन किया जाता है, तो इस प्रकार का ब्याज उस संविदाकारी राज्य में उद्भूत हुआ माना जाएगा जिसमें स्थायी संस्थापन स्थित है।

8. जहां, ब्याज अदाकर्ता तथा हिताधिकारी स्वामी के बीच अथवा उन दोनों और किसी अन्य व्यक्ति के बीच एक विशेष प्रकार का संबंध होने के कारण अदा की गयी ब्याज की रकम, उस ऋण दावे को ध्यान में रखते हुए, जिसके लिए ब्याज की रकम अदा की गयी है, उस रकम से बढ़ जाती है, जिसके लिए इस प्रकार का संबंध नहीं होने की स्थिति में अदाकर्ता और हिताधिकारी स्वामी के बीच सहमति हो गयी होती तो वहां इस अनुच्छेद के उपबंध केवल अंतिम वर्णित रकम पर ही लागू होंगे, उस मामले में, अदायगी के अतिरिक्त भाग पर, इस करार के अन्य उपबंधों का सम्यक अनुपालन करते हुए, प्रत्येक संविदाकारी राज्य के कानून के अनुसार कर लगाया जाएगा।

#### अनुच्छेद 12

रायल्टियां और शामिल की गई सेवाओं के लिए फीस

1. एक संविदाकारी राज्य में उद्भूत होने वाली और दूसरे संविदाकारी राज्य के निवासी को अदा की गयी रायल्टियों और शामिल की गयी सेवाओं के लिए फीस पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकता है।

2. तथापि, इस प्रकार की रायल्टियों और शामिल की गयी सेवाओं के लिए फीस पर उस संविदाकारी राज्य में भी, जिसमें वे उद्भूत होती हों, उस राज्य के कानूनों के अनुसार कर लगाया जा सकता है। लेकिन, यदि रायल्टी अथवा शामिल की गयी सेवाओं के लिए फीस का हिताधिकारी स्वामी दूसरे संविदाकारी राज्य का निवासी है तो इस प्रकार लगाया गया कर निम्नलिखित से अधिक नहीं होगा :

(क) इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 3 के उप-पैराग्राफ (क) में उल्लिखित रायल्टियों और पैराग्राफ 4 के पैराग्राफ (ख) में उल्लिखित शामिल की गयी सेवाओं के लिए फीसों के संबंध में:—

(i) प्रथम पांच करादेय वर्षों के दौरान जिसके लिए यह करार प्रभावित हुआ है ;

(क) शामिल की गयी सेवाओं के लिए रायल्टियों अथवा फीसों की सकल रकम का 15 प्रतिशत, जैसाकि इस अनुच्छेद में परिभाषित है, जहां रायल्टियों अथवा फीसों की अदाकर्ता उस संविदाकारी राज्य की सरकार, कोई राजनैतिक उप-प्रभाग अथवा सार्वजनिक क्षेत्र की कोई कंपनी है ; और

(ख) अन्य सभी मामलों में, शामिल की गयी सेवाओं के लिए रायल्टियों अथवा फीसों की सकल रकम का 20% ; और

(ii) बाद के वर्षों के दौरान, शामिल की गयी सेवाओं के लिए रायल्टियों अथवा फीसों की सकल रकम का 15% ; और

(ख) इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 3 के उप-पैराग्राफ (ख) में उल्लिखित रायल्टियों और पैराग्राफ 4 के उप-पैराग्राफ (क) में उल्लिखित शामिल की गयी सेवाओं के लिए फीसों के संबंध में, ऐसी रायल्टियों अथवा शामिल की गयी सेवाओं के लिए फीसों का सकल रकम का 10%।

3. इस अनुच्छेद में यथा-प्रयुक्त "रायटी" पद से अभिप्रेत है :

(क) साहित्यिक, कलात्मक या वैज्ञानिक कृतियों के किसी भी कापी-राइट के प्रयोग के लिए अथवा प्रयोगाधिकार के लिए, जिनमें विनिर्माण-कृतियों अथवा रेडियो अथवा टेलीविजन प्रसारण के संबंध में इस्तेमाल में आने वाली फिल्में टेपे अथवा पुनः प्रस्तुतीकरण के अन्य साधनों पर कार्य भी शामिल है, कोई पेटेंट, ट्रेड मार्क, डिजाइन अथवा साइल, प्लान, गुप्त फार्मूला अथवा प्रक्रिया अथवा औद्योगिक, वाणिज्यिक अथवा वैज्ञानिक अनुभव से संबंधित जानकारी के लिए प्रतिफल के रूप में प्राप्त किसी भी प्रकार की अदायगी ; और

(ख) किसी औद्योगिक, वाणिज्यिक अथवा वैज्ञानिक उपकरणों के प्रयोग के लिए अथवा प्रयोगाधिकार के लिए प्रतिफल के रूप में प्राप्त किसी भी प्रकार की अदायगी।

4. इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए "शामिल की गयी सेवाओं के लिए फीस" पद से अभिप्रेत है :

(क) किसी तकनीकी अथवा परामर्शदात्री स्वरूप की सेवाएं प्रदान करने के लिए (जिनमें तकनीकी अथवा अन्य कामियों की सेवाओं की व्यवस्था भी शामिल है), प्रतिफल के रूप में किसी व्यक्ति को की जाने वाली किसी किस्म की अदायगियां, यदि ऐसी सेवाएं अनुपंगी हैं और उन अधिकार के उपयोग अथवा उपभोग के लिए सहायक हैं जिनके लिए पैराग्राफ 3 के उप-पैराग्राफ (ख) में वर्णित कोई अदायगी प्राप्त की जाती है ;

(ख) किसी तकनीकी अथवा परामर्शदात्री स्वरूप की सेवाएं प्रदान करने के लिए (जिनमें तकनीकी अथवा अन्य कामियों की सेवाओं की व्यवस्था भी शामिल है), प्रतिफल के रूप में किसी व्यक्ति को की जाने वाली किसी किस्म की अदायगियां, यदि ऐसी सेवाएं :

(i) अनुपंगी हैं और ऐसे अधिकार, संपत्ति अथवा सूचना के उपयोग अथवा उपभोग के लिए सहायक हैं जिनके लिए पैराग्राफ 3 के उप-पैराग्राफ (क) में वर्णित कोई अदायगी प्राप्त की जाती है; अथवा

(ii) तकनीकी ज्ञान, अनुभव, कौशल, जानकारी अथवा प्रक्रियाएं उपलब्ध करायी जाती हैं अथवा जिनमें तकनीकी योजना अथवा तकनीकी डिजाइन का विकास और अन्तर्गण शामिल है ।

5. पैराग्राफ 4 के होते हुए भी, "शामिल की गयी सेवाओं के लिए फीस" में निम्नलिखित के लिए अदा की गयी रकमें शामिल नहीं होंगी :

(क) उन सेवाओं के लिए जो अनुपंगी और सहायक हैं, उनके अतिरिक्त जो संपत्ति की विक्री के लिए अनिवार्य और आवश्यक रूप से जुड़ी हुई हैं ;

(ख) शिक्षण अथवा शिक्षा संस्थाओं के लिए;

(ग) अदायगी करने वाले व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के निजी इस्तेमाल की सेवाओं के लिए; अथवा

(घ) अनुच्छेद 14 के अंतर्गत आने वाली व्यवसायिक सेवाओं के लिए अदायगी करने वाले व्यक्ति के किसी कर्मचारी अथवा किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों की फर्म (किसी कंपनी से भिन्न) को अदा की गयी रकमों ।

6. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंध उस स्थिति में लागू नहीं होंगे यदि राज्यलियां अथवा शामिल की गयी सेवाओं के लिए फीसों का हिताधिकारी स्वामी जो एक संविदाकारी राज्य का निवासी है और हमारे संविदाकारी राज्य में जिसमें राज्यलियां अथवा शामिल की गयी सेवाओं के लिए फीस उद्भूत होती हैं, वहां पर स्थित किसी स्थायी संस्थापन के

माध्यम से कारोबार करता है और संविदा जिनके संबंध में राज्यलियां अथवा शामिल की गयी सेवाओं के लिए फीस अदा की जाती हैं, ऐसे स्थायी संस्थापन के साथ प्रभावी रूप से संबंधित हैं । ऐसे मामले में अनुच्छेद 7 के उपबंध लागू होंगे ।

7. एक संविदाकारी राज्य में राज्यलियों और शामिल की गयी सेवाओं के लिए फीस तब उद्भूत हुई मानी जाएगी, जब अदा करने वाला स्वयं वह राज्य, उसका कोई राजनैतिक उप-प्रभाग उसका स्थानीय प्राधिकरण या उस राज्य का कोई निवासी हो । तथापि, जहां राज्यलियों अथवा शामिल की गयी सेवाओं के लिए फीस अदा करने वाले व्यक्ति का, चाहे वह किसी संविदाकारी राज्य का निवासी हो अथवा नहीं हो, एक संविदाकारी राज्य में ऐसा कोई स्थायी संस्थापन हो जिसके संबंध में राज्यलियों अथवा शामिल की गयी सेवाओं के लिए फीस अदा करने की देन-दारी उठाई गई हो और ऐसी राज्यलियों अथवा शामिल की गयी सेवाओं के लिए फीस ऐसे स्थायी संस्थापन द्वारा वहन की जानी हो, तब ऐसी राज्यलियों अथवा शामिल की गयी सेवाओं के लिए फीस उस संविदाकारी राज्य में उद्भूत हुई मानी जाएगी जिसमें वह स्थायी संस्थापन स्थित है ।

8. जहां अदाकर्ता और हिताधिकारी स्वामी के बीच अथवा उन दोनों और किसी अन्य व्यक्ति के बीच किसी विशेष प्रकार का संबंध होने के कारण अदा की गयी राज्यलियों अथवा शामिल की गयी सेवाओं के लिए फीस की रकम उस रकम से बढ़ जाती है, जो इस प्रकार का संबंध नहीं होने की स्थिति में अदा की गयी होती, वहां उन अनुच्छेद के उपबंध केवल अन्तिम वर्णित रकम पर ही लागू होंगे । ऐसे मामले में, अदा की गयी रकम के अतिरिक्त भाग पर, उस करार के अन्य उपबंधों को सम्पर्क रूप में स्थान में रखते हुए प्रत्येक संविदाकारी राज्य के कानूनों के अनुसार कर लगाया जाएगा ।

#### अनुच्छेद 13

#### पूंजीगत अभिलाष

1. अनुच्छेद 6 में उल्लिखित और हमारे संविदाकारी राज्य में स्थित अचल संपत्ति के अन्तर्गण से एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा प्राप्त अभिलाषों पर उस हमारे राज्य में कर लगाया जा सकता है ।

2. ऐसी अचल संपत्ति के अन्तर्गण से होने वाले अभिलाषों पर जो एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम की हमारे संविदाकारी राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन को कारोबार संपत्ति का एक हिस्सा है, जिसमें किसी ऐसी स्थायी संस्थापन (अर्थात् अथवा पूर्ण उद्यम के साथ) के अन्तर्गण से होने वाले अभिलाष भी शामिल हैं, उस हमारे राज्य में कर लग सकता है ।



3. अन्तरराष्ट्रीय यातायात में चलाए जाने वाले जलयानों अथवा वायुयानों अथवा इस प्रकार के जलयानों अथवा वायुयानों के संचालन से संबंधित चल संपत्ति के अन्तरण से प्राप्त अभिलाभों पर केवल उस संविदाकारी राज्य में कर लगाया जाएगा जिसमें उद्यम की प्रभावी प्रबन्ध-व्यवस्था का स्थान स्थित है।

4. किसी ऐसी कंपनी के शेयरों के अन्तरण से प्राप्त अभिलाभों पर, जिसकी संपत्ति प्रधानतः किसी संविदाकारी राज्य में स्थित अचल संपत्ति हो, उसी राज्य में कर लगाया जा सकेगा।

5. (क) किसी ऐसी कंपनी के शेयरों के अन्तरण से प्राप्त अभिलाभों पर, जो एक संविदाकारी राज्य की निवासी है, केवल उस संविदाकारी राज्य में कर लग सकेगा जिसका अन्तरणकर्ता निवासी है।

(ख) उप-पैराग्राफ (क) के उपबंध के होने हुए भी, भारत किसी ऐसी कंपनी में, जो भारत की निवासी है, शेयरों के अन्तरण से प्राप्त अभिलाभों पर निम्न स्थितियों पर कर लगा सकता है :

(i) यदि उस कंपनी के पूंजीगत स्टॉक की कम से कम 10 प्रतिशत ब्याज की हिस्सेदारी बनती हो; अथवा

(ii) अन्य मामलों में यदि अन्तरण उस राज्य के किसी निवासी को होता है।

इन मामलों में अनुच्छेद 21 के पैराग्राफ 1, उप-पैराग्राफ (ख) के उपबंध लागू होंगे।

6. पैराग्राफ 1, 2, 3, 4 और 5 में उल्लिखित संपत्ति से भिन्न, किसी भी संपत्ति के अन्तरण से प्राप्त अभिलाभों पर केवल उसी संविदाकारी राज्य में कर लगाया जायेगा जिसका अन्तरणकर्ता निवासी है।

#### अनुच्छेद 14

##### व्यक्तिगत सेवाएं

1. अनुच्छेद 15, 17, 18, 19 और 20 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी संविदाकारी राज्य के किसी व्यक्ति निवासी द्वारा किसी नियोजन के संबंध में प्राप्त वेतनों, मजदूरियों और इस प्रकार के अन्य पारिश्रमिक तथा व्यावसायिक सेवाओं अथवा स्वतंत्र के अन्य क्रियाकलापों के संबंध में प्राप्त आय पर केवल उसी राज्य में कर लगेगा जब तक कि नियोजन सेवाएं अथवा क्रियाकलाप दूसरे संविदाकारी राज्य में किए अथवा निष्पादित नहीं किए जाते हों। यदि नियोजन सेवाएं अथवा क्रियाकलाप इस प्रकार किये जाते हैं अथवा निष्पादित किए जाते हैं तो इस प्रकार से प्राप्त पारिश्रमिक अथवा आय पर उस दूसरे राज्य में कर लग सकेगा।

929 GI/95-2

2. पैराग्राफ 1 के उपबंधों के होने हुए भी, एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य में किए गए या निष्पादित नियोजन, सेवाओं अथवा क्रियाकलापों के संबंध में प्राप्त पारिश्रमिक अथवा आय पर केवल प्रथमोल्लिखित राज्य में कर लगेगा, यदि :

(क) प्राप्तकर्ता वित्तीय वर्ष में ऐसी अवधि अथवा अवधियों के लिए दूसरे राज्य में मौजूद रहा हो जो कुल मिलाकर 183 दिन से अधिक न हो;

(ख) पारिश्रमिक अथवा आय किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा अथवा उसकी ओर से अदा की जाती है जो कि दूसरे राज्य का निवासी नहीं हो; और

(ग) पारिश्रमिक अथवा आय उस स्थायी संस्थापन द्वारा वहन नहीं की जाती, जो कि उस व्यक्ति का दूसरे राज्य में है।

3. इस अनुच्छेद के पूर्ववर्ती उपबंधों के होने हुए भी, अन्तरराष्ट्रीय यातायात में संचालित जलयान अथवा वायुयान पर किए गए किसी नियोजन के संबंध में प्राप्त पारिश्रमिक केवल उस संविदाकारी राज्य में काग्रेस होगा जिसमें उस उद्यम का प्रभावी प्रबन्ध-स्थान स्थित है।

#### अनुच्छेद 15

##### निदेशकों की फीस

किसी संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा किसी ऐसी कंपनी के निदेशक मंडल के सदस्य की हैमियत से जो दूसरे संविदाकारी राज्य की निवासी हो, प्राप्त की गयी निदेशकों की फीस तथा इसी प्रकार की श्रदायगियों पर केवल उस दूसरे राज्य में कर लग सकेगा।

#### अनुच्छेद

##### कलाकार और ऐश्लीट

1. अनुच्छेद 7 और 14 के उपबंधों के होने हुए भी, मनोरंजनकर्ताओं (जैसे कि मंच, चलचित्र, रेडियो अथवा दूरदर्शन कलाकारों और संगीतकारों के रूप में) अथवा ऐश्लीटों द्वारा किए गए इस प्रकार के अपने व्यक्तिगत कार्यकलापों से प्राप्त आय पर केवल उस राज्य में कर लगाया जा सकेगा जिसमें ये क्रियाकलाप किए जाते हैं।

2. जहां किसी मनोरंजन अथवा ऐश्लीट द्वारा किसी संविदाकारी राज्य में इस प्रकार किए गए अपने वैयक्तिक क्रियाकलापों के परिणामस्वरूप आय स्वयं उस मनोरंजनकर्ता अथवा ऐश्लीट को प्राप्त नहीं हो अपितु किसी अन्य व्यक्ति को प्राप्त हो, वहां अनुच्छेद 7 और 14 के उपबंधों के होने हुए भी, उस आय पर, उसी संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकता है।

3. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंध उस स्थिति में लागू नहीं होंगे यदि मनोरंजनकर्ता अथवा ऐथ्लीट का संविदाकारी राज्य का दौरा प्रत्यक्ष रूप से अथवा अप्रत्यक्ष रूप से पूर्ण रूप से अथवा पर्याप्त रूप से उस दूसरे संविदाकारी राज्य की सार्वजनिक निधियों से समर्थित हो जिसमें उस दूसरे राज्य का राजनैतिक उप-प्रभाग, स्थानीय प्राधिकरण अथवा नाविक निकाय शामिल है।

#### अनुच्छेद 17

##### पेंशन तथा वापिकियां

1. एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा प्राप्त की गयी किसी पेंशन (अनुच्छेद 17 में उल्लिखित पेंशन से भिन्न) अथवा किसी वापिकी पर केवल उसी राज्य में कर लग सकेगा।

2. "पेंशन" पद का अर्थ है पिछले नियोजन के प्रतिफल के रूप में अथवा सेवाओं के निष्पादन के दौरान चोटग्रस्त होने पर क्षतिपूर्ति के रूप में की गई कोई आबधिक अदायगी।

3. "वापिकी" शब्द का अर्थ उस नियत राशि से है जो धन अथवा धन के मूल्य में पर्याप्त तथा पूर्ण प्रतिफल के लिए अदायगियां करने के किसी दायित्व के अधीन जीवन-पर्यन्त अथवा किसी विनिर्दिष्ट या निश्चित अवधि के दौरान नियत समय पर आबधिक रूप से देय हों।

#### अनुच्छेद 18

##### सरकारी पारिश्रमिक और पेंशन

1. किसी संविदाकारी राज्य की सरकार द्वारा किसी व्यक्ति को, जो उस राज्य का नागरिक है, दूसरे संविदाकारी राज्य में सरकार कार्यकलापों को पूरा करने के लिए की गई सेवाओं के संबंध में, पेंशन से भिन्न, अदा किए गए पारिश्रमिक पर केवल प्रथमोल्लिखित राज्य में कर लग सकेगा।

2. किसी संविदाकारी राज्य की सरकार द्वारा किसी व्यक्ति को, की गई सेवाओं के संबंध में अदा की गई किसी पेंशन पर केवल उसी संविदाकारी राज्य में कर लग सकेगा।

3. इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंध दोनों में से किसी भी संविदाकारी राज्य की सरकार द्वारा लाभ के प्रयोजन के लिए किए गए किसी कारोबार के संबंध में प्रदान की गई सेवाओं के संबंध में अदायगियों पर लागू नहीं होगा।

4. इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए, "सरकार" पद में कोई राज्य सरकार कैंटोन अथवा स्थानीय

अथवा किसी भी संविदाकारी राज्य का नाविक प्राधिकरण और विशेष रूप से भारतीय रिजर्व बैंक और स्विस् नेशनल बैंक शामिल होगा।

#### अनुच्छेद 19

##### विद्यार्थी और प्रशिक्षु

1. किसी विद्यार्थी, अथवा व्यावसायिक प्रशिक्षु, जो एक संविदाकारी राज्य का दौरा करने से तत्काल पूर्व दूसरे संविदाकारी राज्य का निवासी है अथवा था तथा जो प्रथमोल्लिखित राज्य में केवल अपनी शिक्षा, अथवा प्रशिक्षण के प्रयोजनार्थ रहता है, द्वारा अपने अनुरक्षण-शिक्षा अथवा प्रशिक्षण के प्रयोजन के लिए प्राप्त अदायगियों पर उस राज्य में कर नहीं लगेगा बशर्ते कि ऐसी अदायगियां उस राज्य से बाहर के स्रोतों से उद्भूत होती हों।

2. ऐसे अनुदान, छात्रवृत्तियां और नियोजन से प्राप्त पारिश्रमिक, जो कि पैराग्राफ 1 में शामिल नहीं हैं, के संबंध में पैराग्राफ 1 में वर्णित कोई भी विद्यार्थी अथवा व्यवसायिक प्रशिक्षु, ऐसी शिक्षा अथवा प्रशिक्षण के दौरान इनके अलावा सभी छूटों, राहतों अथवा कटौतियों का पात्र होगा जो कि करों के संबंध में उस देश के निवासियों को उपलब्ध हैं जिसका वह दौरा करता है।

#### अनुच्छेद 20

##### प्राध्यापक, अध्यापक और अनुसंधानकर्ता

1. कोई व्यक्ति जो एक संविदाकारी राज्य का निवासी है अथवा था और जो किसी विश्वविद्यालय अथवा अन्य मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थान में शिक्षण अथवा अनुसंधान करने के मूल प्रयोजन के लिए अथवा दोनों के लिए 24 मास से अधिक की अवधि के लिए दूसरे संविदाकारी राज्य का दौरा करता है, की विश्व-विद्यालय अथवा मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्था में शिक्षण अथवा अनुसंधान के लिए अपनी व्यक्तिगत सेवाओं से होने वाली आय दूसरे संविदाकारी राज्य में कर से छूट प्राप्त होगी।

2. यदि ऐसा अनुसंधान मुख्यतः किसी विशिष्ट व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के निजी लाभ के लिए किया जाना हो तो उस अनुसंधान से प्राप्त आय पर यह अनुच्छेद लागू नहीं होगा।

#### अनुच्छेद 21

##### दोहरे कराधान का अपाकरण

1. (क) समय-समय पर प्रवृत्त भारत के कानून के ऐसे उपबंधों के अधीन रहते हुए तथा जो भारत से बाहर के किसी देश में अदा

किये गए करों की राहत से संबंधित हों, जहाँ भारत का कोई निवासी ऐसी आय प्राप्त करता है, जिस पर इस करार के उपबंधों के अनुसार स्विटजरलैंड में कर लग सकता हो, वहाँ भारत, चाहे प्रत्यक्ष रूप से अथवा कटौती के द्वारा उस निवासी की आय पर, स्विटजरलैंड में अदा की गई आयकर की रकम के बराबर की रकम पर कर से कटौती की अनुमति देगा। तथापि, ऐसी कटौती की रकम, आयकर (कटौती दिये जाने से पूर्व यथा संगणित) के उस भाग से अधिक नहीं होगी जो कि ऐसी आय के कारण हो जिस पर स्विटजरलैंड में कर लगाया जा सकता है।

(ख) जहाँ स्विटजरलैंड का कोई निवासी शेषों के अन्तरण से ऐसे अभिलाभ प्राप्त करता है जिस पर अनुच्छेद 13, पैराग्राफ 5, उप-पैराग्राफ (ख) के अनुसार, भारत में कर लग सकता है, भारत उस आय पर कर से कटौती की अनुमति देगा जो इन पूंजीगत अभिलाभों पर स्विटजरलैंड में अदा किए गये आयकर की रकम के बराबर होगी। तथापि, यह कटौती भारतीय आयकर के उस भाग से अधिक नहीं होगी जो इन पूंजीगत अभिलाभों पर लगाया गया है।

2. (क) जहाँ स्विटजरलैंड का कोई निवासी ऐसी आय प्राप्त करता है जिस पर इस करार के उपबंधों के अनुसार भारत में कर लग सकता है, स्विटजरलैंड उप-पैराग्राफ ख, ग, तथा घ के अनुसार ऐसी आय पर कर से छूट प्रदान करेगा, परन्तु ऐसे निवासी की शेष आय पर कर की गणना करते समय कर की उस दर को लागू करेगा जो इस प्रकार छूट प्राप्त नहीं होने की स्थिति में छूट प्राप्त आय पर लागू होती। तथापि, बशर्ते अनुच्छेद 13 के पैराग्राफ 4 में उल्लिखित अभिलाभों पर ऐसी छूट तभी लागू होगी यदि ऐसे अभिलाभों का वास्तविक कराधान भारत में निरूपित होता हो।

(ख) जहाँ स्विटजरलैंड का कोई निवासी लाभार्थ, व्याज, रायल्टियाँ अथवा शामिल की गई सेवाओं के लिए फीस प्राप्त करता है, जिस पर अनुच्छेद 10, 11 तथा 12 के उपबंधों के अनुसार भारत में कर लग सकता हो, वहाँ स्विटजरलैंड ऐसे निवासी को अनुगोध पर राहत की अनुमति देगा। राहत में निम्नलिखित सम्मिलित हो सकेंगे-

(i) अनुच्छेद 10, 11 तथा 12 के उपबंधों के अनुसार भारत में लगाये गये कर के बराबर की रकम

के बराबर ऐसे निवासी की आय पर स्विस कर से लगाया कोई क्रेडिट तथापि, ऐसा क्रेडिट स्विस कर के उस भाग से अधिक नहीं होगा जो क्रेडिट दिए जाने से पहले यथा संगणित किया गया हो तथा उप-आय के उपयुक्त हो जिस पर भारत में कर लग सकता हो; अथवा

(ii) स्विस पर से एकमुश्त कटौती; अथवा

(iii) स्विस कर में ऐसे लाभार्थों, व्याज, रायल्टियों अथवा शामिल की गई सेवाओं के लिए फीस की आंशिक छूट, किसी भी स्थिति में लाभार्थों, व्याज अथवा रायल्टियों तथा शामिल की गई सेवाओं के लिए फीस की सकल रकम से कम से कम भारत में लगाये गये कर की कटौती की रकम सम्मिलित हो।

स्विटजरलैंड लागू होने योग्य राहत का निर्धारण करेगा तथा दोहरे कराधान के परिहार के लिए स्विस कन्फर्ड-रेशन के अंतर्राष्ट्रीय अभिमतियों को कार्यान्वित करने के संबंध में स्विस उपबंधों के अनुसार पद्धति का विनियमन करेगा।

(ग) उप-पैराग्राफ (ख) के उपबंधों के होते हुए भी, जहाँ स्विटजरलैंड का कोई निवासी व्याज, रायल्टियाँ अथवा सम्मिलित सेवाओं के लिये फीस प्राप्त करता है, जिस पर अनुच्छेद 11 के पैराग्राफ 2 और 12, पैराग्राफ 2, उप-पैराग्राफ (क) के अनुसार भारत में कर लगाया जा सकता है, स्विटजरलैंड अनुगोध किये जाने पर, ऐसे निवासी को राहत की अनुमति देगा जिसमें निम्नलिखित शामिल हो:-

(i) "क" अनुच्छेद 11, पैराग्राफ 2 में उल्लिखित ऐसे व्याज की सकल राशि के 5 प्रतिशत का कटौती;

"ख" पहले पाँच कैलेंडर वर्षों के दौरान जिनके लिये यह करार प्रभावी है;

(1) अनुच्छेद 12, पैराग्राफ 2, उप-पैराग्राफ (क) (i) "क" में उल्लिखित शामिल की गयी सेवाओं के लिये रायल्टियाँ और फीस;

"कक" अनुच्छेद 12, पैराग्राफ 4 उप-पैराग्राफ "ख" (i) द्वारा सम्मिलित की गयी सेवाओं के लिये रायल्टियों अथवा फीसों की सकल राशि के 5 प्रतिशत की कटौती;

"खख" अनुच्छेद 12 पैराग्राफ 4, उप-पैराग्राफ "ख" (ii) द्वारा सम्मिलित की गयी सेवाओं के लिये फीसों की सकल राशि के 10 प्रतिशत की कटौती;

(2) अनुच्छेद 12, पैराग्राफ 2, उप-पैराग्राफ (क) (i) में उल्लिखित शामिल की गयी सेवाओं के लिये रायल्टियों और फीसों हेतु ;

“कक” अनुच्छेद 12, पैराग्राफ 4, उप-पैराग्राफ “ख” (i) द्वारा शामिल की गयी सेवाओं के लिये रायल्टियों अथवा फीसों की सकल राशि के 10 प्रतिशत की कटौती ;

“खख” अनुच्छेद 12, पैराग्राफ 4, उप-पैराग्राफ “ख” (ii) द्वारा सम्मिलित की गयी सेवाओं के लिये फीसों की सकल राशि के 15 प्रतिशत की कटौती ;

(ग) बाद के उन वर्षों के दौरान जिनके लिये यह करार प्रभावी है :

“कक” अनुच्छेद 12, पैराग्राफ 4, उप-पैराग्राफ “ख” (i) द्वारा सम्मिलित सेवाओं के लिये अनुच्छेद 12, पैराग्राफ 2, उप-पैराग्राफ “क” (ii) में उल्लिखित रायल्टियों अथवा फीस के लिये इनकी सकल राशि के 5 प्रतिशत की कटौती ;

“खख” अनुच्छेद 12, पैराग्राफ 4, उप-पैराग्राफ “ख” (ii) द्वारा सम्मिलित की गयी सेवाओं के लिये फीसों की सकल राशि के 10 प्रतिशत की कटौती ;

(ii) पूर्ववर्ती उप-पैराग्राफ में उल्लिखित राहत के संदर्भ में यथा-संगणित उस निवासी की आय पर स्विस् कर से निम्नोक्त राशि का क्रेडिट ;

क. अनुच्छेद 11, पैराग्राफ 2, में उल्लिखित ब्याज की सकल राशि का 10 प्रतिशत ;

ख. अनुच्छेद 12, पैराग्राफ 2, उप-पैराग्राफ “क” में उल्लिखित रायल्टियों और अनुच्छेद 12, पैराग्राफ 4, उप-पैराग्राफ “ख” (i) द्वारा सम्मिलित की गयी सेवाओं के लिये फीसों की सकल राशि का 10 प्रतिशत ;

(ग) अनुच्छेद 12, पैराग्राफ 4, उप-पैराग्राफ “ख” (ii) द्वारा सम्मिलित की गयी सेवाओं के लिये फीसों की सकल राशि का 5 प्रतिशत ;

तथापि, इस पैराग्राफ के उप-पैराग्राफ “ख” में उल्लिखित राहत के सामान्य सिद्धान्तों के अनुसार ही ऐसे क्रेडिट का निर्धारण किया जायेगा ।

(घ) जहाँ स्विटजरलैंड का कोई निवासी ऐसा ब्याज प्राप्त करता है जिस पर भारतीय आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(4) और 10(15)(4)(ग) के अन्तर्गत विवेचन किया गया हो और जिसका उल्लेख अनुच्छेद 11, पैराग्राफ 4, उप-पैरा (घ) में किया गया है, अनुरोध करने पर स्विटजरलैंड ऐसे निवासी

को ब्याज की सकल राशि के 10 प्रतिशत की राशि के बराबर तक राहत की अनुमति देगा ।

अनुच्छेद 22

सम-व्यवहार

1. एक संविदाकारी राज्य के राष्ट्रियों पर दूसरे संविदाकारी राज्य में ऐसा कोई कराधान अथवा तत्संबंधी ऐसी कोई अपेक्षा लागू नहीं होगी, जो उन कराधान से और उनसे संबंधित अपेक्षाओं से भिन्न अथवा अपेक्षाकृत अधिक भारपूर्ण हो, जो उस दूसरे राज्य के राष्ट्रियों पर एक-समान परिस्थितियों तथा एक-समान शर्तों में लागू होती हैं अथवा हो सकती हैं ।

2. इस अनुच्छेद में निहित किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि एक संविदाकारी राज्य के उन व्यक्तियों को उपकृत करता है जो उस राज्य के निवासी नहीं हैं, कराधान के प्रयोजनार्थ किसी प्रकार को व्यक्तिगत छूट राहत और कटौतियों मंजूर करने के लिये, जो कि कानून द्वारा केवल ऐसे व्यक्तियों को उपलब्ध हैं जो वहाँ के निवासी हैं ।

3. एक संविदाकारी राज्य के उद्यमों पर जिनकी पूंजी पूर्णतः अथवा अंशतः दूसरे संविदाकारी राज्य के एक अथवा एक से अधिक निवासियों के प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष स्वामित्व में अथवा नियंत्रण में है, प्रथमोक्त संविदाकारी राज्य में वैसी ही परिस्थितियों और वैसी ही शर्तों के अधीन ऐसा कोई कराधान अथवा तत्संबंधी कोई भी अपेक्षा लागू नहीं की जायेगी, जो उस कराधान से तथा तत्संबंधी किन्हीं भी अपेक्षाओं से भिन्न अथवा अपेक्षाकृत अधिक भारपूर्ण है, जो प्रथमोल्लिखित राज्य के अन्य समरूप उद्यमों पर लगाई जाती है अथवा लगाई जा सकती है ।

4. इस अनुच्छेद में, “कराधान” पद से अभिप्राय उन करों से है जो इस करार के विषय हैं ।

अनुच्छेद 23

पारस्परिक करार कार्यविधि

1. जहाँ किसी संविदाकारी राज्य का निवासी यह समझता है कि एक अथवा दोनों संविदाकारी राज्यों की कार्यवाहियों के कारण उस पर इस प्रकार कर लगाया जाता है अथवा लगाया जायेगा जो कि इस करार के अनुकूल नहीं है, तो वह, उन राज्यों के स्वदेशी कानूनों द्वारा उपलब्ध कराये गये उपचारों के होते हुए भी उस संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी को अपना मामला प्रस्तुत कर सकता है जिसका यह एक निवासी है । यह मामला उस कार्यवाही की प्रथम अधिसूचना के तीन वर्षों के भीतर अवश्य प्रस्तुत कर दिया जाना चाहिये जिसके परिणामस्वरूप ऐसा कराधान हुआ है जो इस करार के अनुरूप नहीं है ।

2. यदि सक्षम प्राधिकारी को आपत्ति उचित लगे और यदि वह स्वयं किसी उपयुक्त हल पर पहुंचने में असमर्थ हो तो वह ऐसे कराधान के निवारण की दृष्टि से, जो इस करार के अनुरूप नहीं है, दूसरे संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी के साथ परस्पर सहमति ढांग उस मामले को हल करने का प्रयास करेगा।

3. यदि उस करार की व्याख्या करने में अथवा उसे लागू करने में कोई कठिनाइयां अथवा शंकाएं उत्पन्न हों तो संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी उन्हें पारस्परिक सहमति से हल करने का प्रयास करेंगे। वे उन मामलों में भी बोहरे कराधान के अपाकरण के लिए परस्पर विचार-विमर्श कर सकते हैं जिनकी इस करार में व्यवस्था नहीं की गई है।

4. दोनों संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी पारस्परिक सहमति से अनुच्छेद 10, 11 और 12 के लिए रखी गई सीमाओं को लागू करने के तरीके निपटाएंगे।

5. पूर्ववर्ती पैराग्राफों के अभिप्राय से कोई समझौता करने के प्रयोजनार्थ संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी एक-दूसरे के साथ सीधे पत्र-व्यवहार भी कर सकते हैं। यदि किसी समझौते पर पहुंचने के उद्देश्य से मौखिक मतों का आदान-प्रदान उपयुक्त हो तो ऐसे आदान-प्रदान संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारियों के प्रतिनिधियों के किसी आयोग के माध्यम से किए जा सकते हैं।

#### अनुच्छेद 24

##### सूचना का आदान-प्रदान

1. संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी ऐसी सूचना (ऐसी सूचना जो कि प्रशासन की प्रक्रिया में उनके संबंधित कराधान कानूनों के तहत उनके अधिकार में है) का आदान-प्रदान करेंगे जो कि करों से संबंधित इस करार के उपबंधों, जो कि इस करार के विषय हैं, को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक है। इस प्रकार आदान-प्रदान की जाने वाली सूचना गुप्त मानी जाएगी और, करों के निर्धारण और वसूली, जो कि इस करार के विषय हैं, से संबंधित व्यक्तियों के अलावा किसी को प्रकट नहीं की जाएगी, उपर्युक्त ऐसी कोई कोई सूचना का आदान-प्रदान नहीं किया जाएगा जिससे कोई व्यापारिक, व्यावसायिक, औद्योगिक अथवा व्यावसायिक भेद, व्यापारिक प्रक्रिया प्रकट होती हो।

7. किसी भी स्थिति में इस अनुच्छेद के उपबंधों का अर्थ किसी भी संविदाकारी राज्य पर ऐसा दायित्व डालना नहीं होगा जिससे किसी भी संविदाकारी राज्य के विनियमों और प्रथा से हटकर प्रशासनिक उपाय करना अथवा जो कि उसकी प्रभुसत्ता, सुरक्षा अथवा सार्वजनिक नीति के विपरीत हो अथवा ऐसे व्यौरों को प्रस्तुत करना जो कि

इसके अथवा लागू करने वाले राज्य के अपने विधानों के तहत प्राप्त नहीं किए जा सकते हों।

#### अनुच्छेद 25

##### राजनयिक तथा कौंसुली अधिकारी

इस करार को किसी भी बात से राजनयिक अथवा कौंसुली अधिकारियों को अन्तर्राष्ट्रीय कानून के सामान्य नियमों के अन्तर्गत अथवा विशेष करारों के उपबंधों के अन्तर्गत प्राप्त विनियम विशेषाधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं होगा।

#### अनुच्छेद 26

##### प्रवर्तन

1. यह करार तब लागू होगा जब दोनों संविदाकारी राज्य राजनयिक माध्यमों से एक-दूसरे को यह सूचित करेंगे कि उन्होंने इस करार को प्रभावी बनाने के लिये सभी कानूनी अपेक्षाएं और कार्यवाहियों को पूरा कर लिया है।

7. यह करार ऐसी सूचना देने पर लागू हो जायेगा और इसके उपबंधों का निम्नलिखित प्रभाव होगा :

(क) भारत में, जिस कैलेंडर वर्ष में लागू करार होता है उसके अनुवर्ती वर्ष के लिये अप्रैल माह के प्रथम दिन को अथवा उसके बाद आरम्भ होने वाले किसी वित्तीय वर्ष में अवभूत होने वाली आय के संबंध में; और

(ख) स्विटजरलैंड में, जिस कैलेंडर वर्ष में करार लागू होता है उसके अनुवर्ती वर्ष के जनवरी माह के प्रथम दिन को अथवा उसके बाद आरम्भ होने वाले किसी वित्तीय वर्ष में उद्भूत होने वाली आय के संबंध में।

3. पैराग्राफ 2 के अनुसार जब इस करार के उपबंध लागू हो जायेंगे तो वायुयान का परिचालन करने वाले उद्यमों के कराधान के संबंध में नई दिल्ली में 28 अगस्त, 1958, को भारत सरकार तथा स्विस संघीय परिषद के बीच सम्पन्न करार (जिसे इस अनुच्छेद में 1958 का करार कहा गया है) उन करों पर लागू नहीं रहेगा जिन पर यह लागू होता है।

4. वर्ष 1958 का करार उस अन्तिम तारीख की समाप्ति पर समाप्त हो जायेगा जिस तारीख को यह इस अनुच्छेद के पूर्ववर्ती उपबंधों के अनुसार प्रभावी हो।

अनुच्छेद 27

समापन

यह करार अनिश्चित समय तक लागू रहेगा लेकिन दोनों में से कोई भी एक संविदाकारी राज्य किसी कैलेंडर वर्ष के जून माह की तीस तारीख को अथवा उससे पूर्व दूसरे संविदाकारी राज्य को करार के समापन की सूचना दे सकता है और ऐसी परिस्थिति में यह करार निम्नलिखित के संबंध में निष्प्रभावी हो जायेगा:

- (क) भारत में, जिस कैलेंडर वर्ष में करार के समापन की सूचना दी जाती है उसके अनुवर्ती वर्ष के अप्रैल माह के प्रथम दिन को अथवा उसके बाद आरम्भ होने वाले किसी वित्तीय वर्ष में उद्भूत होने वाली आय के संबंध में, और
- (ख) स्विटजरलैंड में, जिस कैलेंडर वर्ष में करार के समापन की सूचना दी जाती है उसके अनुवर्ती वर्ष के जनवरी माह के प्रथम दिन को अथवा उसके बाद आरम्भ होने वाले किसी वित्तीय वर्ष में उद्भूत होने वाली आय के संबंध में

जिसके माध्य में, इसके लिये विधिवत् रूप में प्राधिकृत अधोहस्ताक्षरियों ने इस करार पर हस्ताक्षर किये हैं।

नई दिल्ली में वर्ष एक हजार नौ सौ चौरानवे के नवम्बर माह के दूसरे दिन हिन्दी, जर्मन और अंग्रेजी भाषाओं में दो-दो प्रतियों में निष्पन्न किया गया तथा सभी पाठ समान रूप में प्रामाणिक हैं। आशंका की स्थिति में अंग्रेजी पाठ सर्वोपरि होगा।

भारत गणराज्य की सरकार      स्विस् संघीय परिषद  
की ओर से      की ओर से

हस्ताक्षर अपटनीय

प्रोताकोल

आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार के लिए भारत गणराज्य और स्विस् परिसंघ के बीच हुए करार के लिए प्रोताकोल।

आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार के लिए स्विस् संघीय परिषद और भारत गणराज्य की सरकार के बीच आज निष्पन्न हुए करार पर हस्ताक्षर करते समय, अधोहस्ताक्षरकर्ता निम्नलिखित अनिश्चित उपबंधों पर सहमत हो गए हैं जो उक्त करार के अमिल अंग होंगे:—

#### 1. अनुच्छेद 5 के संबंध में

यह समझा जाता है कि पैराग्राफ 2 के उप-पैराग्राफ 1 के अन्तर्गत होने वाली सेवाओं को प्रस्तुत करने के लिए

पारिथमिक पर (अनुच्छेद 7) के अनुसार अथवा उद्यम के अन्तर्गत पर (अनुच्छेद 12 के पैराग्राफ 2, उप-पैराग्राफ क) में बनाई गई दरों के अनुसार कर लगाया जाएगा।

अनुच्छेद 5 के पैराग्राफ 3 के संबंध में यह समझा जाता है कि डिलिवरी के प्रयोजनार्थ मात्र अथवा पण्य-वस्तुओं का कोई स्टॉक रखना अथवा माल और पण्य-वस्तुओं की डिलिवरी के लिए इस्तेमाल की गई सुविधाएं कोई स्थायी संस्थापन तथा तक नहीं बनाती है जब तक कि उक्त अनुच्छेद के पैराग्राफ 2 अथवा 4 की शर्तें पूरी नहीं होती हैं।

अनुच्छेद 5 के पैराग्राफ 4 के संबंध में यह समझा जाता है कि ऐसा कोई व्यक्ति जो किसी संविदाकारी राज्य में पूर्णतः अथवा लगभग पूर्णतः उस उद्यम के लिए निरन्तर रूप से आर्डर प्राप्त करता है, केवल उस उद्यम का स्थायी संस्थापन माना जाएगा यदि ऐसा व्यक्ति माल अथवा पण्य-वस्तुओं की खरीद करने वाले व्यक्तियों का निरन्तर प्रतिनिधित्व करता है और ऐसे व्यक्ति द्वारा किसी आर्डर को स्वीकृति आर्डर में विनिर्दिष्ट शर्तों के अन्तर्गत माल अथवा पण्य-वस्तुओं की सप्लाई उद्यम के संबंध में करार निष्पादित करती है।

#### 2. अनुच्छेद 7 के संदर्भ में

अनुच्छेद 7 के पैराग्राफ 1 के संबंध में यह समझा जाता है कि इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए "प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः" शब्दों से यह अभिप्रेत है कि जहां कोई स्थायी संस्थापन उद्यम द्वारा प्रवृत्त बातचीत करने संविदाएं निष्पन्न करने अथवा पूरी करने में सक्रिय भाग लेता है तब उद्यम के अन्य भागों को उन सौदों में शामिल कर दिए जाने के बावजूद उन संविदाओं में से उद्भूत होने वाले उद्यम के लाभों का वह अनुपात स्थायी संस्थापन के लिए आरोपणीय होगा क्योंकि उन सौदों के लिए स्थायी संस्थापन का अंगदान पूर्ण रूप से उस उद्यम को वहन करता है। यह भी समझा जाता है कि लाभों को उपर्युक्त सीमा तक स्थायी संस्थापन के लिए आरोप्य समझा जाएगा चाहे प्रतंगत संविदाएं स्थायी संस्थापन की अपेक्षा उद्यम के प्रधान कार्यालय के साथ सीधे किए जाते हैं।

किसी संविदाकारी राज्य में औद्योगिक, वाणिज्यिक अथवा वैज्ञानिक उपकरण अथवा परिमरों अथवा लोक कार्यों, जो किसी स्थायी संस्थापन रखने वाली किसी उद्यम द्वारा चलाए जाते हैं, के सर्वेक्षण, सप्लाई, प्रतिष्ठान अथवा निर्माण कार्य के लिए संविदाओं के मामले में ऐसे स्थायी संस्थापन के कारोबार संबंधी लाभों को संविदा की कुल रकम के आधार पर निर्धारित नहीं किया जाएगा बल्कि संविदा के उस भाग के आधार पर ही निर्धारित किया जाएगा जो उस राज्य में स्थायी संस्थापन द्वारा कारगर रूप से चलाया जाता है जहां स्थायी संस्थापन स्थित है, संविदा के उस भाग से संबंधित लाभों पर जो उस संविदाकारी राज्य के बाहर उद्यम के प्रधान कार्यालय द्वारा चलाया जाता है, केवल उस राज्य में कर लगाया जाएगा अहां उद्यम कोई निवासी है बशर्ते कि देय रकम अनुच्छेद 12 के उपबंधों के अंतर्गत शामिल नहीं होती है।

## 3. अनुच्छेद 10, 11 और 12 के संदर्भ में

भारत और किसी तीसरे राज्य के बीच, जो ओ. ई. सी. डी. का सदस्य है, किसी अभिसमय अथवा करार के अन्तर्गत इस करार पर हस्ताक्षर किये जाने के बाद लाभार्थी, व्याज, रायल्टियों अथवा शामिल की गई सेवाओं के लिए फीसों पर अपेक्षाकृत कम दर अथवा उस दर अथवा क्षेत्र में सीमित अधि-क्षेत्र के लिए, स्रोत पर उसके कगधान को सीमित करता है जैसा कि आय की उक्त मदों पर इस करार में व्यवस्था है, तो स्विटजरलैण्ड और भारत, स्विटजरलैण्ड को वैसा ही व्यवहार देने के लिए बिना सम्यक विलम्ब के बातचीत कर सकेंगे जैसा कि तीसरे राज्य के साथ व्यवहार किया जाता है।

## 4. अनुच्छेद 12 के संदर्भ में

यह समझा जाता है कि अनुच्छेद 12 के पैराग्राफ 3 के उप-पैराग्राफ (क) में उल्लिखित किसी अधिकार अथवा किसी सम्पत्ति के अन्तरण से प्राप्त किए गए अभिलाभों पर अनुच्छेद 7 अथवा अनुच्छेद 13 के अनुसार कर लगाया जा सकता है। तथापि, ऐसे किसी अधिकार अथवा सम्पत्ति के अन्तरण से प्राप्त अभिलाभों पर, जो लाभों, उत्पादकता अथवा उसके उपयोग पर आश्रित हैं, अनुच्छेद 12 के अनुसार कर लग सकता है।

## 5. अनुच्छेद 23 के संदर्भ में

पैराग्राफ 2 के संदर्भ में यह समझा जाता है कि यदि पारस्परिक करार संबंधी प्रक्रिया कर निर्धारण के अन्तिम रूप में होने के समय से पांच वर्षों के भीतर लागू कर दिया गया है तब किया गया कोई करार संविदाकारी राज्यों के घरेलू नियमों में किसी समय सीमा के होते हुए भी क्रियान्वित किया जाएगा।

जिसके साक्ष्य में, इसके लिए विधिवत रूप से प्राधिकृत अधिकृतारियों ने मौजूदा प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं।

नई दिल्ली में वर्ष एक हजार नौ सौ चौरानवें के नवम्बर माह के दूसरे दिन हिन्दी, जर्मन और अंग्रेजी भाषाओं में दो दो प्रतियों में निम्न किया गया, सभी पाठ समान रूप में प्रमाणिक हैं, आगवा की स्थिति में अंग्रेजी पाठ सर्वोपरि होगा।

भारत गणराज्य की  
सरकार की ओर से  
टी. एस. श्रीनिवासन  
अध्यक्ष, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड  
वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

स्विस संघीय परिषद  
की ओर से  
जॉ पियर जेन्डर  
भारत में स्विटजरलैण्ड  
के राजदूत

[अधिसूचना सं. 9752/फा. सं. 501/7/73-एफ.टी.डी.]  
बी. बी. श्रीनिवासन, संयुक्त सचिव (एफटीएंडटीआर)

## MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

## NOTIFICATION

New Delhi, the 21st April, 1995

## INCOME-TAX

G.S.R. 357(E).—Whereas the annexed Agreement between the Government of the Republic of India and the Government of the Swiss Confederation for the avoidance of double taxation with respect to taxes on Income has entered into force on 29th December, 1994 after the notification by both the Contracting States to each other of the completion of the procedures required under their laws for bringing into force of the said Agreement in accordance with paragraph 1 of Article 26 of the said Agreement;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 90 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) the Central Government hereby directs that all the provisions of the said Agreement shall be given effect to in the Union of India.

## AGREEMENT

## BETWEEN

THE REPUBLIC OF INDIA

## AND

THE SWISS CONFEDERATION

FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION  
WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME

THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA

## AND

THE SWISS FEDERAL COUNCIL

DESIRING to conclude an Agreement for the avoidance of double taxation with respect to taxes on income,

HAVE AGREED as follows :

## Article 1

## Personal scope

This Agreement shall apply to persons who are residents of one or both of the Contracting States.

## Article 2

## Taxes covered

1. The taxes to which this Agreement shall apply are:

(a) In the case of India:

the income tax including any surcharge thereon; and

(b) In the case of Switzerland: the federal, cantonal and communal taxes on income (total income, earned income from capital, industrial and commercial profits, capitals gains, and other items of income).

2. The Agreement shall also apply to any identical or substantially similar taxes which are imposed by either Contracting State after the date of signature of the present Agreement in addition to, or in place of, the taxes referred to in paragraph 1 of this Article.

3. In this Agreement, the term "Indian tax" means tax imposed by India, being tax to which this Agreement applies; the term "Swiss tax" means tax imposed in Switzerland, being tax to which this Agreement applies; and the term "tax" means Indian tax or Swiss tax, as the context requires; but the taxes in the preceding paragraphs of this Article do not include any penalty or interest imposed under the law in force in either Contracting State relating to the taxes to which this Agreement applies.

4. The competent authorities of the Contracting States shall notify to each other any significant changes which have been made in their relevant respective taxation laws;

### Article 3

#### General definitions

1. In this Agreement, unless the context otherwise requires:

- (a) the term "India" means the territory of India and includes the territorial sea and the air space above it, as well as any other maritime zone in which India has sovereign rights, other rights and jurisdictions, according to the Indian law and in accordance with international law;
- (b) the term "Switzerland" means the Swiss Confederation;
- (c) the terms "a Contracting States" and "the other Contracting State" mean India or Switzerland as the context requires;
- (d) the term "person" includes an individual, a company, a body of persons, or any other entity which is taxable under the laws in force in either Contracting States;
- (e) the term "company" means any body corporate or any entity which is treated as a company under the taxation laws of the respective Contracting States;
- (f) the terms "enterprise of Contracting State" and "enterprise of the other Contracting State" mean, respectively, an enterprise carried on by a resident of a Contracting State and an enterprise carried on by a resident of the other Contracting State;
- (g) the term "competent authority" means, in the case of India, the Central Government in the Department of Revenue or their authorised representative, and, in the case of Switzerland, the Director of the Federal Tax Administration or his authorised representative;
- (h) the term "national" means any individual possessing the nationality of a Contracting State and any legal person, partnership or association deriving its status from the laws in force in the Contracting State;
- (i) the term "international traffic" means any transport by an aircraft operated by an enterprise of a Contracting State, except when the aircraft is operated solely between places in the other Contracting State;
- (j) the term "operation of aircraft" shall mean business of transportation by air of passengers, mail, livestock or goods carried on by the owners or lessees or charterers of aircraft, including the sale of tickets for such transportation on behalf of other enterprises, the incidental lease of aircraft and any other activity directly connected with such transportation;
- (k) the term "fiscal year" means :
  - (i) in the case of India, the "previous year" as defined in the Income-tax Act of India; and
  - (ii) in the case of Switzerland, the calendar year.

2. In the application of the provisions of this Agreement by a Contracting State, any term not defined therein shall, unless the context otherwise requires, have the meaning which it has under the laws in force in that State relating to the taxes which are the subject of this agreement.

### Article 4

#### Fiscal domicile

1. For the purposes of this Agreement, the term "resident of a Contracting State" means any person who, under the laws of that State, is liable to taxation therein by reason of his domicile, residence, place of incorporation, place of management or any other criterion of a similar nature.

2. Where by reason of the provisions of paragraph 1, an individual is a resident of both Contracting States, then his residential status for the purposes of this Agreement shall be determined in accordance with the following rule :

- (a) he shall be deemed to be a resident of the Contracting State in which he has a permanent home available to him. If he has a permanent home available to him in both Contracting States, he shall be deemed to be a resident of the Contracting State with which his personal and economic relations are closer (hereinafter referred to as his "centre of vital interests");
- (b) if the Contracting State in which he has his centre of vital interest cannot be determined or if he does not have a permanent home available to him in either Contracting State, he shall be deemed to be a resident of the Contracting State in which he has an habitual abode;
- (c) if he has an habitual abode in both Contracting States or in neither of them, he shall be deemed to be a resident of the Contracting State of which he is a national;
- (d) if he is a national of both Contracting States or of neither of them, the competent authorities of the Contracting States shall settle the question by mutual agreement.

3. Where by reason of the provisions of paragraph 1, a person other than an individual is a resident of both Contracting States, then it shall be deemed to be a resident of the Contracting State in which its place of effective management is situated.

### Article 5

#### Permanent establishment

1. For the purpose of this Agreement, the term "permanent establishment" means a fixed place of business through which the business of the enterprise is wholly or partly carried on.

2. The term "permanent establishment" shall include especially :

- (a) a place of management;
- (b) a branch;
- (c) an office;
- (d) a store or other sales outlet;
- (e) a factory;
- (f) a workshop;
- (g) a warehouse in relation to a person providing storage facilities for others;
- (h) a permanent sales exhibition;
- (i) a mine, a quarry, an oil or gas well, or any other place of extraction of natural resources;
- (j) a building site or construction, installation or assembly project or supervisory activities connection therewith, where such site, project or supervisory activity continues for a period of more than six months;
- (k) an installation or structure used for the exploration or development of natural resources for more than 90 days; and



(j) the furnishing of services other than included services as defined in Article 12, within a Contracting State by an enterprise through employees, or other personnel, but only if;

(i) activities of that nature continue within that State for a period or periods aggregating more than 90 days within any twelve-month period; or

(ii) the services are performed within that State for a related enterprise (within the meaning of paragraph 1 of Article 9) for a period or periods aggregating more than 30 days within any twelve-month period.

3. The term "permanent establishment" shall not be deemed to include :

(a) the use of facilities solely for the purpose of storage or display of goods or merchandise belonging to the enterprise;

(b) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of storage or display;

(c) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of processing by another enterprise;

(d) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of purchasing goods or merchandise or for collecting information, for the enterprise;

(e) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of advertising, for the supply of information or for scientific research, being activities solely of a preparatory or auxiliary character in the trade or business of the enterprise.

4. A person acting in a Contracting State for or on behalf of an enterprise of the other Contracting State—other than an agent of an independent status to whom paragraph 5 applies—shall be deemed to be a permanent establishment of that enterprise in the first-mentioned State if :

(i) he has and habitually exercises in that State, an authority to negotiate and enter into contracts for or on behalf of the enterprise, unless his activities are limited to the purchase of goods or merchandise for the enterprise; or

(ii) he habitually maintains in the first-mentioned Contracting State a stock of goods or merchandise from which he regularly delivers goods or merchandise for or on behalf of the enterprise; or

(iii) in so acting, he manufactures or processes in that State for the enterprise goods or merchandise belonging to the enterprise, provided that this provision shall apply only in relation to the goods or merchandise so manufactured or processed.

5. An enterprise of a Contracting State shall not be deemed to have a permanent establishment in the other Contracting State merely because it carries on business in that other State through a broker, general commission agent or any other agent of an independent status, where such persons are acting in the ordinary course of their business. However, when the activities of such an agent are devoted wholly or almost wholly on behalf of that enterprise or for the enterprise and other enterprises which are controlled by it or have a controlling interest in it, he would not be considered an agent of an independent status within the meaning of this paragraph.

6. The fact that a company, which is a resident of a Contracting State controls or is controlled by a company

which is a resident of other Contracting State, or which carries on business in that other Contracting State (whether through a permanent establishment or otherwise), shall not, of itself, constitute for either company a permanent establishment of the other.

#### Article 6

##### Income from immovable property

1. Income from immovable property may be taxed in the Contracting State in which such property is situated.

2. The term "immovable property" shall be defined in accordance with the law of the Contracting State in which the property is situated. The term shall in any case include property accessory to immovable property, livestock and equipment used in agriculture and forestry, rights to which the provisions of general law respecting landed property apply, usufruct of immovable property and rights to variable or fixed payments as consideration for the working of, or the right to work, mineral deposits, oilwells, quarries and other places of extraction of natural resources. Ships and aircraft shall not be regarded as immovable property.

3. The provisions of paragraph 1 shall apply to income derived from the direct use, letting, or use in any other form of immovable property.

4. The provisions of paragraphs 1 and 3 shall also apply to the income from immovable property of an enterprise and to income from immovable property used for the performance of professional services.

#### Article 7

##### Business profits

1. The business profits of an enterprise of a Contracting State, other than the profits from the operation of ships in international traffic, shall be taxable only in that State unless the enterprise carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein. If the enterprise carries on business as aforesaid, the profits of the enterprise may be taxed in the other State but only so much of them as is directly or indirectly attributable to that permanent establishment.

2. Where an enterprise of a Contracting State carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, there shall in each Contracting State be attributed to that permanent establishment the profits which it might be expected to make if it were a distinct and separate enterprise engaged in the same or similar activities under the same or similar conditions and dealing wholly independently with the enterprise of which it is a permanent establishment.

3. In the determination of the profits of a permanent establishment, there shall be allowed as deductions expenses which are incurred for the purposes of permanent establishment, whether in the State in which the permanent establishment is situated or elsewhere. Executive and general administrative expenses shall be allowed as deductions in accordance with the taxation laws of that State. Nothing in paragraph 3 shall, however, authorise a deduction for expenses which would not be deductible if the permanent establishment were a separate enterprise.

4. In so far as it has been customary in a Contracting State to determine the profits to be attributed to a permanent establishment on the basis of an apportionment of the total profits of the enterprise to its various parts, nothing in paragraph 2 shall preclude that Contracting State from determining the profits to be taxed by such an apportionment as may be customary; the method of apportionment adopted shall, however, be such that the result shall be in accordance with the principles laid down in this Article.

5. No profits shall be attributed to a permanent establishment by reason of the mere purchase by that permanent establishment of goods or merchandise for the enterprise.

6. Where profits include items of income which are dealt with separately in other Articles of this Agreement, then the provisions of those Articles shall not be affected by the provisions of this Article.

#### Article 8

##### Air transport

1. Profits from the operation of aircraft in international traffic shall be taxable only in the Contracting State in which the place of effective management of the enterprise is situated.

2. The provisions of paragraph 1 shall also apply to profits from the participation in a pool, a joint business or an international operating agency.

#### Article 9

##### Associated enterprises

##### Where

- (a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of the other Contracting State, or
- (b) the same persons participate directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of a Contracting State and an enterprise of the other Contracting State.

and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their commercial or financial relations which differ from those which would be made between independent enterprises, then any profits which would, but for those conditions have accrued to one of the enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.

#### Article 10

##### Dividends

1. Dividends paid by a company which is a resident of a Contracting State to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such dividends may also be taxed in the Contracting State of which the company paying the dividends is a resident and according to the laws of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the dividends the tax so charged shall not exceed 15 per cent of the gross amount of the dividends.

This paragraph shall not affect the taxation of the company in respect of the profits out of which the dividends are paid.

3. The term "dividends" as used in this Article means income from shares "jouissance" shares or "jouissance" rights, mining shares, founders' shares or other rights, not being debt-claims, participating in profits, as well as income from other corporate rights, which is subjected to the same taxation treatment as income from shares, by the taxation law of the State of which the company making the distribution is a resident.

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the dividends, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State of which the company paying the dividends is a resident, through a permanent establishment situated therein and the holding in respect of which the

dividends are paid is effectively connected with such permanent establishment. In such a case the provisions of Article 7 shall apply.

5. Where a company which is a resident of a Contracting State derives profits or income from the other Contracting State, that other State may not impose any tax on the dividends paid by the company, except insofar as such dividends are paid to a resident of that other State or insofar as the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with a permanent establishment situated in that other State, nor subject the company's undistributed profits to a tax on the company's undistributed profits, even if the dividends paid or the undistributed profits consist wholly or partly of profits or income arising in such other State.

#### Article 11

##### Interest

1. Interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such interest may also be taxed in the Contracting State in which it arises, and according to the laws of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the interest the tax so charged shall not exceed 15 per cent of the gross amount of interest.

3. Notwithstanding the provisions of paragraph 2, where the interest is paid to a bank carrying on a bona fide banking business or to an enterprise which holds directly or indirectly at least 20 per cent of the capital of the company paying the interest which are a resident of the other Contracting State and are the beneficial owner of the interest the tax so charged in the Contracting State in which the interest arises shall not exceed 10 per cent of the gross amount of the interest.

4. Notwithstanding the provisions of paragraphs 2 and 3.

(a) interest arising in Switzerland and paid to a resident of India shall be taxable only in India if it is paid in respect of a loan made, guaranteed or insured, or a credit extended, guaranteed or insured by the Export-Import Bank of India or by any institution specified and agreed in letters exchanged between the competent authorities of the Contracting States.

(b) interest arising in India and paid to a resident of Switzerland shall be taxable only in Switzerland if it is paid in respect of a loan made, guaranteed or insured, or a credit extended, guaranteed or insured under the Swiss provisions regulating the Export or Investment Risk Guarantee or by any institution specified and agreed in letters exchanged between the competent authorities of the Contracting States;

(c) interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State engaged in the operation of aircraft in international traffic shall be taxable only in that other State to the extent that such interest is paid on funds connected with such activity;

(d) interest arising in India and paid to a resident of Switzerland shall be exempt from Indian tax if the loan or other indebtedness in respect of which the interest is paid is an approved loan. The term "approved loan" means any loan or other indebtedness approved by the Government of India in this behalf.

5. The term "interest" as used in this Article means income from debt-claims of every kind, whether or not secured by mortgage and whether or not carrying a right

to participate in the debtor's profits, and in particular, income from government securities and income from bonds or debentures, including premiums and prizes attaching to such securities, bonds or debentures. Penalty charges for late payment shall not be regarded as interest for the purpose of this Article.

6. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the interest, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the interest arises, through a permanent establishment situated therein, and the debt-claim in respect of which the interest is paid is effectively connected with such permanent establishment. In such a case the provisions of Article 7 shall apply.

7. Interest shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that State itself, a political subdivision, a local authority or a resident of that State. Where, however, the person paying the interest, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment in connection with which the indebtedness on which the interest is paid was incurred, and such interest is borne by such permanent establishment, then such interest shall be deemed to arise in the Contracting State in which the permanent establishment is situated.

8. Where, owing to a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the interest paid, having regard to the debt-claim for which it is paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In that case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the law of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Agreement.

## Article 12

### Royalties and Fees For Included Services

1. Royalties and fees for included services arising in a Contracting state and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such royalties and fees for included services may also be taxed in the Contracting State in which they arise and according to the laws of that State; but if the beneficial owner of the royalties or fees for included services is a resident of the other Contracting State, the tax so charged shall not exceed:

(a) in the case of royalties referred to in sub-paragraph (a) of paragraph 3 and fees for included services referred to in sub-paragraph (b) of paragraph 4 of this Article;

(i) during the first five taxable years for which this Agreement has effect.

(A) 15 per cent of the gross amount of the royalties or fees for included services as defined in this Article, where the payer of the royalties or fees is the Government of that Contracting State, a political sub-division or a public sector company; and

(B) 20 per cent of the gross amount of the royalties or fees for included services in all other cases; and

(ii) during the subsequent years, 15 per cent of the gross amount of royalties or fees for included services; and

(b) in the case of royalties referred to in sub-paragraph (b) of paragraph 3 and fees for included services referred to in sub-paragraph (a) of paragraph

4 of this Article 10 per cent of the gross amount of such royalties or fees for included services.

3. The term "royalties" as used in this Article means:

(a) payments of any kind received as a consideration for the use of, or the right to use, any copyright of a literary, artistic, or scientific work, including cinematograph films or work on film, tape or other means of reproduction for use in connection with radio or television broadcasting, any patent trademark, design or model, plan, secret formula or process, or for information concerning industrial, commercial or scientific experience; and

(b) payments of any kind received as consideration for the use of, or the right to use, any industrial, commercial, or scientific equipment.

4. For purposes of this Article the term "fees for included services" means:

(a) payments of any kind to any person in consideration for the rendering of any technical or consultancy services (including through the provision of services of technical or other personnel) if such services are ancillary and subsidiary to the application or enjoyment of the right, for which a payment described in sub-paragraph (b) of paragraph 3 is received;

(b) payments of any kind to any person in consideration for the rendering of any technical or consultancy services (including through the provision of services of technical or other personnel) if such services:

(i) are ancillary and subsidiary to the application or enjoyment of the right, property or information for which a payment described in sub-paragraph (a) of paragraph 3 is received; or

(ii) make available technical knowledge, experience, skill, know-how or processes, or consist of the development and transfer of a technical plan or technical design.

5. Notwithstanding paragraph 4, "fees for included services" does not include amounts paid:

(a) for services that are ancillary and subsidiary, as well as inextricably and essentially linked, to the sale of property;

(b) for teaching in or by educational institutions;

(c) for services for the personal use of the individual or individuals making the payment; or

(d) to an employee of the person making the payments or to any individual or firm of individuals (other than a company) for professional services falling under Article 14.

6. The provisions of 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the royalties or fees for included services, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the royalties or fees for included services arise, through a permanent establishment situated therein and the contract in respect of which the royalties or fees for included services are paid is effectively connected with such permanent establishment. In such case, the provisions of Article 7 shall apply.

7. Royalties and fees for included services shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that State itself, a political sub-division, a local authority or a resident of that State. Where, however, the person paying the royalties or fees for included services, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment in connection

with which the liability to pay the royalties or fees for included services was incurred, and such royalties or fees for included services are borne by such permanent establishment, then such royalties or fees for included services shall be deemed to arise in the State in which the permanent establishment is situated.

8. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the royalties or fees for included services paid exceeds the amount which would have been paid in the absence of such relationship, the provisions of this article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Agreement.

#### Article 13

##### Capital Gains

1. Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of immovable property referred to in Article 6 and situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. Gains from the alienation of movable property forming part of the business property of permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State, including such gains from the alienation of such a permanent establishment (alone or with the whole enterprise), may be taxed in that other State.

3. Gains from the alienation of ships or aircraft operated in international traffic, or movable property pertaining to the operation of such ships or aircraft, shall be taxable only in the Contracting State in which the place of effective management of the enterprise is situated.

4. Gains from the alienation of shares of a company, the property of which consists principally of immovable property situated in a Contracting State, may be taxed in that State.

5. (a) Gains from the alienation of shares in a company which is a resident of a Contracting State shall be taxable only in the Contracting state of which the alienator is a resident.

(b) Notwithstanding the provision of sub-paragraph (a), India may tax gains from the alienation of shares in a company which is a resident of India.

(i) if the shares form part of at least a 10 per cent interest in the capital stock of that company, or

(ii) in other cases if the alienation takes place to a resident of that State.

In these cases the provisions of paragraph 1, sub-paragraph (b) of Article 21 shall apply.

6. Gains from the alienation of any property other than that referred to in paragraphs 1, 2, 3, 4 and 5, shall be taxable only in the Contracting State of which the alienator is a resident.

#### Article 14

##### Personal Services

1. Subject to the provisions of Articles 15, 17, 18, 19 and 20, salaries, wages and other similar remuneration in respect of an employment as well as income in respect of professional services or other activities of an independent character, derived by an individual resident of a Contracting State, shall be taxable only in that State, unless the employment, services or activities are exercised or performed in the other Contracting State. If the employment, services or activities are so exercised or performed, such remuneration or income as is derived therefrom may be taxed in that other State.

2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, remuneration or income derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment, services or activities exercised or performed in the other Contracting State shall be taxable only in the first-mentioned State if:

(a) the recipient is present in the other State for a period or periods not exceeding in the aggregate 183 days in the fiscal year, and

(b) the remuneration or income is paid by, or on behalf of, a person who is not a resident of the other State, and

(c) the remuneration or income is not borne by a permanent establishment which that person has in the other State.

3. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, remuneration derived in respect of an employment exercised aboard a ship or aircraft operated in international traffic shall be taxable only in the Contracting State in which the place of effective management of the enterprise is situated.

#### Article 15

##### Directors' Fees

Directors' fees and similar payments derived by a resident of a Contracting State in his capacity as a member of the Board of Directors of a company which is a resident of the other Contracting State shall be taxable only in that other Contracting State.

#### Article 16

##### Artists and Athletes

1. Notwithstanding the provisions of Articles 7 and 14 income derived by entertainers (such as stage, motion picture, radio or television artists and musicians) or athletes, from their personal activities as such shall be taxable only in the Contracting State in which these activities are exercised.

2. Where income as a result of personal activities as such exercised in a Contracting State by an entertainer or athlete accrues not to that entertainer or athlete himself but to another person, that income may, notwithstanding the provisions of Articles 7 and 14, be taxed in that Contracting State.

3. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the visit to a Contracting State of the entertainer or the athlete is directly or indirectly supported, wholly or substantially, from the public funds of the other Contracting State, including any political sub-division, local authority or statutory body of that other State.

#### Article 17

##### Pension and Annuities

1. Any pension (other than a pension referred to in Article 18) or annuity derived by a resident of a Contracting State shall be taxable only in that State.

2. The term "pension" means a periodic payment made in consideration of past employment or by way of compensation for injuries received in the course of the performance of services.

3. The term "annuity" means a stated sum payable periodically at stated times, during life or during a specified or ascertainable period of time, under an obligation to make the payments in return for adequate and full consideration in money or money's worth.

## Article 18

## Government remuneration and pensions

1. Remuneration, other than a pension, paid by the Government of a Contracting State to any individual who is a citizen of that State in respect of services rendered in the discharge of governmental functions in the other Contracting State shall be taxable only in the first-mentioned State.

2. Any pension paid by the Government of a Contracting State to any individual in respect of services rendered shall be taxable only in that Contracting State.

3. The provisions of paragraphs 1 and 2 of this Article shall not apply to payments in respect of services rendered in connection with any business carried on by the Government of either of the Contracting States for the purpose of profit.

4. For the purposes of this Article, the term "Government" shall include any State Government, canton or local or statutory authority of either Contracting State and in particular the Reserve Bank of India and the Swiss National Bank.

## Article 19

## Students and apprentices

1. Payments which a student or business apprentice who is or was immediately before visiting a Contracting State a resident of the other Contracting State and who is present in the first-mentioned State solely for the purpose of his education or training receives for the purpose of his maintenance, education or training shall not be taxed in that State, provided that such payments arise from sources outside that State.

2. In respect of grants, scholarships and remuneration from employment not covered by paragraph 1, a student or business apprentice described in paragraph 1 shall, in addition be entitled during such education or training to the same exemptions, reliefs or reductions in respect of taxes available to residents of the State which he is visiting.

## Article 20

## Professors, Teachers and Researchers

1. An individual who is or was a resident of a Contracting State and who visits the other Contracting State for a period not exceeding 24 months for the primary purpose of teaching or engaging in research, or both, at a university or other recognised educational institution shall be exempt from tax in that other Contracting State on his income from personal services for teaching or research at the university or the recognised educational institution.

2. This Article shall not apply to income from research if such research is undertaken primarily for the private benefit of a specific person or persons.

## Article 21

## Elimination of double taxation

1. (a) Subject to any provisions of the law of India which may from time to time be in force and which relates to the relief of taxes paid in a country outside India, where a resident of India derives income which, in accordance with the provisions of this Agreement, may be taxed in Switzerland, India shall allow as a deduction from the tax on the income of that resident an amount equal to the income tax paid in Switzerland whether directly or by deduction. Such deduction shall not, however, exceed that part of the income tax (as computed before the deduction is given) which is attributable to the income which may be taxed in Switzerland.

(b) Where a resident of Switzerland derives gains from the alienation of shares which may be taxed in India according to Article 13, paragraph 5, sub-paragraph (b) India

shall allow as a deduction from tax on that income, an amount equal to the income tax paid in Switzerland on these capital gains. The deduction shall not, however, exceed that part of the Indian income tax, which is imposed on these capital gains.

2. (a) Where a resident of Switzerland derives income which, in accordance with the provisions of this Agreement may be taxed in India, Switzerland shall, subject to the provisions of sub-paragraphs (b), (c) and (d), exempt such income from tax but may, in calculating tax on the remaining income of that resident, apply the rate of tax which would have been applicable if the exempted income had not been so exempted; provided, however, that such exemption shall apply to gains referred to in paragraph 4 of Article 13 only if actual taxation of such gains in India is demonstrated.

(b) Where a resident of Switzerland derives dividends, interest, royalties or fees for included services which, in accordance with the provisions of Articles 10, 11 and 12, may be taxed in India, Switzerland shall allow, upon request, a relief to such resident. The relief may consist of:

- (i) a credit from the Swiss tax on the income of that resident of an amount equal to the tax levied in India in accordance with the provisions of Articles 10, 11 and 12; such credit shall not, however, exceed that part of the Swiss tax, as computed before the credit is given, which is appropriate to the income which may be taxed in India; or
- (ii) a lump sum reduction of the Swiss tax; or
- (iii) a partial exemption of such dividends, interest, royalties or fees for included services from Swiss tax, in any case consisting at least of the deduction of the tax levied in India from the gross amount of the dividends, interest, royalties or fees for included services.

Switzerland shall determine the applicable relief and regulate the procedure in accordance with the Swiss provisions relating to the carrying out of international conventions of the Swiss Confederation for the avoidance of double taxation.

(c) Notwithstanding the provisions of sub-paragraph (b), where a resident of Switzerland derives interest, royalties or fees for included services which, in accordance with Articles 11, paragraph 2 and 12, paragraph 2, sub-paragraph (a) may be taxed in India, Switzerland shall allow, upon request, a relief to such resident which may consist of:

- (i) A. a deduction of 5 per cent of the gross amount of such interest referred to in Article 11, paragraph 2;
- B. during the first five calendar years for which this Agreement has effect,
- (1) for royalties and fees for included services referred to in Article 12, paragraph 2, sub-paragraph (a) (i) (A):
- (aa) a deduction of 5 per cent of the gross amount of royalties or of fees for included services covered by Article 12, paragraph 4, sub-paragraph (b) (i);
- (bb) a deduction of 10 per cent of the gross amount of fees for included services covered by Article 12, paragraph 4, sub-paragraph (b) (ii);
- (2) for royalties and fees for included services referred to in Article 12, paragraph 2, sub-paragraph (a) (i) (B):
- (aa) a deduction of 10 per cent of the gross amount of royalties or of fees for included services covered by Article 12, paragraph 4, sub-paragraph (b) (i);

- (bb) a deduction of 15 per cent of the gross amount of fees for included services covered by Article 12, paragraph 4, sub-paragraph (b) (ii);

C. during the subsequent years for which this Agreement has effect:

- (aa) a deduction of 5 per cent of the gross amount of royalties referred to in Article 12, paragraph 2, sub-paragraph (a) (ii) or of fees for included services covered by Article 12, paragraph 4, sub-paragraph (b) (i);

- (bb) a deduction of 10 per cent of the gross amount of fees for included services covered by Article 12, paragraph 4, sub-paragraph (b) (ii);

(ii) a credit from the Swiss tax on the income of that resident, as computed by reference to the relief referred to in the foregoing sub-paragraph of an amount of:

- A. 10 per cent of the gross amount of the interest referred to in Article 11, paragraph 2;

- B. 10 per cent of the gross amount of the royalties referred to in Article 12, paragraph 2, sub-paragraph (a), and of the fees for included services covered by Article 12, paragraph 4, sub-paragraph (b) (i);

- C. 5 per cent of the gross amount of the fees for included services covered by Article 12, paragraph 4, sub-paragraph (b) (ii).

Such credit shall, however, be determined pursuant to the general principles of the relief referred to in sub-paragraph (b) of this paragraph.

(d) Where a resident of Switzerland derives interest dealt with in section 10(4) and 10(15) (iv) (c) of the Indian Income Tax Act of 1961 and referred to in Article 11, paragraph 4, sub-paragraph (d), Switzerland shall allow, upon request, a relief to such resident of an amount equal to 10 per cent of the gross amount of the interest

#### Article 22

##### Non-discrimination

1. The nationals of a Contracting State shall not be subjected in the other Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which nationals of that other State in the same circumstances and under the same conditions are or may be subjected.

2. Nothing contained in this Article shall be construed as obliging a Contracting State to grant to persons not residents in that State any personal allowances, reliefs and reductions for taxation purposes which are by law available only to persons who are so resident.

3. Enterprises of a Contracting State, the capital of which is wholly or partly owned or controlled, directly or indirectly, by one or more residents of the other Contracting State, shall not be subjected in the first-mentioned Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than taxation and connected requirements to which other similar enterprises of that first-mentioned State are or may be subjected in the same circumstances and under the same conditions.

4. In this Article, the term "taxation" means taxes which are the subject of this Agreement.

#### Article 23

##### Mutual agreement procedure

1. Where a resident of a Contracting State considers that the actions of one or both of the Contracting States result or will result for him in taxation not in accordance with this Agreement, he may, notwithstanding the remedies

provided by the national laws of those States, present his case to the competent authority of the Contracting State of which he is a resident. The case must be presented within three years from the first notification of the action giving rise to taxation not in accordance with the Agreement.

2. The competent authority shall endeavour, if the objection appears to it to be justified and if it is not itself able to arrive at an appropriate solution, to resolve the case by mutual agreement with the competent authority of the other Contracting State, with a view to the avoidance of taxation which is not in accordance with the Agreement.

3. The competent authorities of the Contracting States shall endeavour to resolve by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application of the Agreement. They may also consult together for the elimination of double taxation in cases not provided for in the Agreement.

4. The competent authorities of the Contracting States shall settle the limitations provided for in Articles 10, 11 and 12.

5. The competent authorities of the Contracting States may communicate with each other directly for the purpose of reaching an agreement in the sense of the preceding paragraphs. When it seems advisable in order to reach agreement to have an oral exchange of opinions, such exchange may take place through a Commission consisting of representatives of the competent authorities of the Contracting States.

#### Article 24

##### Exchange of Information

1. The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information (being information which is at their disposal under their respective taxation laws in the normal course of administration) as is necessary for carrying out the provisions of this Agreement in relation to the taxes which are the subject of this Agreement. Any information so exchanged shall be treated as secret and shall not be disclosed to any persons other than those concerned with the assessment and collection of the taxes which are the subject of this Agreement. No information as aforesaid shall be exchanged which would disclose any trade, business, industrial or professional secret or trade process.

2. In no case shall the provisions of this Article be construed as imposing upon either of the Contracting States the obligation to carry out administrative measures at variance with the regulations and practice of either Contracting State or which would be contrary to its sovereignty, security or public policy or to supply particulars which are not procurable under its own legislation or that of the State making application.

#### Article 25

##### Diplomatic and consular officials

Nothing in this Agreement shall affect the fiscal privileges of diplomatic or consular officials under the general rules of international law or under the provisions of special agreements.

#### Article 26

##### Entry into force

1. This Agreement shall come into force when the Contracting States have notified each other through diplomatic channels that all legal requirements and procedures for giving effect to this Agreement have been satisfied.

2. This Agreement shall enter into force upon the date of such notification and its provisions shall have effect:

- (i) in India, in respect of income arising in any fiscal year beginning on or after the first day of April

next following the calendar year in which the Agreement enters into force; and

- (b) in Switzerland, in respect of income arising in any fiscal year beginning on or after the first day of January next following the calendar year in which the Agreement enters into force.

3. The Agreement between the Government of India and the Swiss Federal Council concerning the taxation of enterprises operating aircraft signed at New Delhi on 28 August 1958 (in this Article called "the 1958 Agreement") shall cease to have effect with respect to taxes to which the Agreement applies when the provisions of this Agreement become effective in accordance with paragraph 2.

4. The 1958 Agreement shall terminate on the expiration of the last date on which it has effect in accordance with the foregoing provisions of this Article.

#### Article 27

##### Termination

This Agreement shall continue in effect indefinitely but either of the Contracting States may, on or before the thirtieth day of June in any calendar year, give notice of termination to the other Contracting States and, in such event this Agreement shall cease to be effective:

- (a) in India, in respect of income arising in any fiscal year beginning on or after the first day of April next following the calendar year in which the notice of termination is given; and
- (b) in Switzerland, in respect of income arising in any fiscal year beginning on or after the first day of January next following the calendar year in which the notice of termination is given.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorised thereto, have signed the present Agreement.

Done in duplicate at New Delhi this 2nd day of November, one thousand nine hundred and ninety four in the Hindi, German, and English languages, all the texts being equally authentic, except in the case of doubt when the English text shall prevail.

For the Government of  
the Republic of India:

For the Swiss  
Federal Council:

#### PROTOCOL

to the Agreement between the Republic of India and the Swiss Confederation for the avoidance of double taxation with respect to taxes on income.

At the signing of the Agreement concluded to-day between the Government of the Republic of India and the Swiss Federal Council for the avoidance of double taxation with respect to taxes on income, the undersigned have agreed upon the following additional provisions which shall form an integral part of the said Agreement.

##### 1. With reference to Article 5

It is understood that the remuneration for furnishing of services covered by the sub-paragraph (1) of paragraph 2 shall be taxed according to Article 7 or, on request of the enterprise, according to the rates provided for in paragraph 2, sub-paragraph (a) of Article 12.

With respect to paragraph 3 of Article 5 it is understood that the maintenance of a stock of goods or merchandise for the purpose of delivery, or facilities used for delivery of goods and merchandise do not constitute a permanent establishment as long as the conditions of paragraphs 2 or 4 of the same Article are not fulfilled.

With respect to paragraph 4 of Article 5 it is understood that a person who habitually secures orders in a Contracting State wholly or almost wholly for the enterprise itself, shall be deemed to be a permanent establishment of that enterprise only if such person habitually represents to persons offering to buy goods or merchandise that acceptance of an order by such person constitutes the agreement of the enterprise to supply goods or merchandise under the terms and conditions specified in the order.

##### 2. With reference to Article 7

With respect to paragraph 1 of Article 7 it is understood that the words "directly or indirectly" mean, for the purposes of this Article, that where a permanent establishment takes an active part in negotiating, concluding or fulfilling contracts entered into by the enterprise, then, notwithstanding that other parts of the enterprise have also participated in those transactions there shall be attributed to the permanent establishment that proportion of profits of the enterprise arising out of those contracts as the contribution of the permanent establishment to those transactions bears to that of the enterprise as a whole. It is also understood that profits shall be regarded as attributable to the permanent establishment to the above-mentioned extent, even when the contracts in question are made directly with the head office of the enterprise rather than with the permanent establishment.

In the case of contracts for the survey, supply, installation or construction of industrial, commercial or scientific equipment or premises, or of public works, which are carried out by an enterprise having a permanent establishment, in a Contracting State the business profits of such permanent establishment shall not be determined on the basis of the total amount of the contract, but shall be determined only on the basis of that part of the contract which is effectively carried out by the permanent establishment situated; the profits related to that part of the contract which is carried out outside that Contracting State by the head office of the enterprise shall be taxable only in the State of which of the enterprise is a resident, provided that the amount payable is not covered under the provisions of Article 12.

##### 3. With reference to Article 10, 11 and 12

It is understood that after the signature of this Agreement under any Convention or Agreement between India and a third State which is a member of the OECD India should limit its taxation at source on dividends, interests, royalties or fees for included services to a rate lower or a scope more restricted than the rate or scope provided for in this Agreement on the said items of income, then, Switzerland and India shall enter into negotiations without undue delay in order to provide the same treatment to Switzerland as that provided to the third State.

##### 4. With reference to Article 12

It is understood that gains derived from the alienation of 12 may be taxed according to Article 7 or Article 13. However, gains derived from the alienation of any such right or property which are contingent on the profits, productivity or use thereof may be taxed according to Article 12.

## 5. With reference to Article 23

With respect to paragraph 2 it is understood that if the mutual agreement procedure has been introduced within five years from the moment when tax assessment became final, then any agreement reached shall be implemented notwithstanding any time limits in the domestic law of the Contracting States.

In witness whereof the undersigned, being duly authorised thereto, have signed the present Protocol.

Done in duplicate at New Delhi this 2nd day of November, one thousand nine hundred and ninety four in the Hindi, German and English languages, all the texts being

equally authentic, except in the case of doubt when the English text shall prevail.

For the Government of  
the Republic of India:

(T. S. SRINIVASAN)

Chairman,

Central Board of Direct Taxes

Ministry of Finance.

Notification No. 9752/F. No. 501/7/73-FTD.

For the Swiss Federal Council

(JEAN-PIERRE ZEHNDER)

Ambassador of Switzerland  
in India.

V. B. SRINIVASAN, Jt. Secy. (FT&TR)